



सीबीएसई की चेतावनी

12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते डमी स्कूलों के विद्यार्थी



नई दिल्ली। डमी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती। नियमित स्कूल न जाने की जिम्मेदारी भी संबंधित विद्यार्थियों और अभिभावकों पर है। सीबीएसई के एक अधिकारी ने यह बताना दिया है। उन्होंने बताया कि नियमित स्कूल न जाने वाले विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा के लिए रेफर करने वाले स्कूलों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे विद्यार्थियों को 12वीं बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी, जिनकी 75

प्रतिशत अटेंडेंस नहीं होगी। बोर्ड के अधिकारी ने कहा कि डमी स्कूलों में प्रवेश के दुष्परिणामों की जिम्मेदारी खुद स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की होगी। सीबीएसई डमी स्कूलों के खिलाफ जारी कार्रवाई के तहत परीक्षा उपनियमों में बदलाव करने पर विचार कर रही है। ताकि ऐसे छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं में बैठने से रोका जा सके। इन्हें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयीन शिक्षा संस्थान की परीक्षा देनी होगी। अधिकारी के अनुसार, अगर कोई परीक्षार्थी स्कूल से गायब पाया जाता है या बोर्ड द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित

पाया जाता है, तो ऐसे परीक्षार्थियों को बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नियमित तौर पर कक्षाओं में शामिल नहीं होने के कारण यह फैसला लिया जा रहा है, ऐसे में इसके जिम्मेदार विद्यार्थी और उसके अभिभावक होंगे। अधिकारी ने यह भी कहा कि 'डमी संस्कृति' को बढ़ावा देने वाले या गैर-हाजिर छात्रों को आगे बढ़ाने वाले विद्यालयों के खिलाफ बोर्ड की संबद्धता और परीक्षा के अनुसार के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यह मुद्दा बोर्ड की हाल ही में हुई शासकीय बोर्ड बैठक में भी उठवाया गया था, जहां यह सिफारिश की गई थी कि इस निर्णय को शैक्षणिक सत्र 2025-2026 से लागू किया जाए। सीबीएसई ने पिछले साल दिसंबर 2024 में दिल्ली, बंगलुरु, वाराणसी, बिहार, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 29 स्कूलों में 'डमी' विद्यार्थियों के नामांकन की जांच के लिए कई औचक निरीक्षण किए थे। इनमें कई विद्यार्थी स्कूल में अनुपस्थित मिले थे। बोर्ड ने कई स्कूलों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था।

उज्जैन में राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन में बोले सीएम डॉ. मोहन यादव

मप्र की स्पेस पॉलिसी बनाए जाएगी, इसरो सेंटर शुरू करने की कोशिश

उज्जैन। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में स्पेस पॉलिसी का निर्माण किया जाएगा और इसरो के केंद्र की स्थापना के लिए प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने यह बात गुरुवार को उज्जैन में आयोजित राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन और चालीसवें मध्यप्रदेश युवा वैज्ञानिक सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान वरुंचल रूप से कही। इस सम्मेलन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। डॉ. यादव ने कहा कि भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बड़ा योगदान दिया है, खासकर डिफेंस और अंतरिक्ष के क्षेत्र में। उन्होंने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की नीति को भारत के इस क्षेत्र में सफलता का कारण बताया। मध्यप्रदेश भी इस क्षेत्र में नए अवसरों की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शीघ्र ही स्पेस पॉलिसी बनाई जाएगी और इसरो के एक केंद्र की स्थापना पर विचार शुरू किया गया है।



सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और कहा कि प्रदेश में इसरो की तरह एक केंद्र स्थापित करने की योजना है। प्रदेश में बढ़ रहा ड्रोन तकनीक का उपयोग मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में ड्रोन तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है, खासकर कृषि क्षेत्र में, और राजस्व विभाग में भूमि सर्वेक्षण के लिए ड्रोन का उपयोग शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उज्जैन को काल गणना का केंद्र बताते हुए कहा कि यह शहर न केवल सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान का भी केंद्र है। उन्होंने युवा वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्राचीन भारतीय विज्ञान परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, आज के विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार की जरूरत है। उन्होंने

यह भी कहा कि हाल ही में घोषित चार नीतियां, जैसे मध्यप्रदेश ड्रोन संवर्धन नीति-2025, एमिशन और गेमिंग नीति-2025, सेमी कंडक्टर नीति-2025 और वैश्विक क्षमता केंद्र नीति-2025, प्रदेश को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक मजबूत आधार देने के लिए बनाई गई हैं। कौशल प्रशिक्षण के लिए जल्द होगा अनुबंध राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद के निदेशक डॉ. प्रकाश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव वैज्ञानिक सोच रखते हैं, जिस तरह देश डिफेंस प्रोडक्शन, स्पेस और बायो टेक्नालॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, मध्यप्रदेश भी इन क्षेत्रों में प्रयासरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेस पॉलिसी-2023 लाने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ऐसे चंद मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं जो इस क्षेत्र में नवाचार

के लिए उत्साहित हैं। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए शीघ्र ही मेपकास्ट के सहयोग से अनुबंध किया जाएगा। कृषि बीमा योजना जैसे कार्य स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहे हैं। कई वैज्ञानिक और कुलगुरु हुए शामिल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक डॉ. अनिल कोठारी ने कहा कि प्रदेश में इस तरह के वैज्ञानिक सम्मेलन अन्य स्थानों पर भी किए जाएंगे। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलगुरु राकेश सिंघाई, विक्रमादित्य शोध पीठ के निदेशक और मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार श्रीराम तिवारी, विक्रम विश्वविद्यालय के कुलगुरु भारती के राष्ट्रीय महासचिव विवेकानंद पई, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के एमिटीएस वैज्ञानिक सुधीर मिश्रा और महानिदेशक, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल प्रो. गोवर्धन दास, निदेशक नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन डॉ. अरविन्द रानाडे, प्रमुख सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग, प्रोफेसर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर प्रो. मनीष जैन भी सम्मेलन में शामिल हुए। समत्व भवन से मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी के संचालक अशोक कडेल और अपर मुख्य सचिव सूचना प्रौद्योगिकी संजय दुबे भी सम्मेलन के इस सत्र में उपस्थित हुए।

महंगी होने वाली हैं एंटीबायोटिक, कैंसर और डायबिटीज की दवाइयां

नई दिल्ली। दवा की कीमत को काबू में रखने के लिए सरकार ने कई दवाओं को प्राइस कंट्रोल लिस्ट में डाला है। सरकार का दावा है कि इस कारण मरीजों को सालाना करीब 3,788 करोड़ रुपए की बचत होती है। लेकिन अब सरकार के नियंत्रण वाली दवाइयां महंगी हो सकती हैं। इनमें कैंसर, डायबिटीज, दिल की बीमारियों और एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इन दवाओं की कीमत में 1.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) देश में दवाओं की कीमतें तय करती है। कीमतों में बढ़ोतरी से दवा कंपनियों को राहत मिलेगी लेकिन मरीजों की मुश्किल बढ़ेगी। ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रुगिस्ट्स (एआईओसीडी) के महासचिव राजीव सिंघेल ने बताया कि इस कदम से दवा कंपनियों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि कच्चे माल और अन्य खर्चों की लागत बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि दवाओं की नई कीमतों का बाजार में असर



दो से तीन महीने में देखने को मिलेगा। इसकी वजह यह है कि बाजार में दवाओं का करीब 90 दिनों का स्टॉक रहता है। यानी अगले कई महीनों तक बाजार में पुरानी कीमत पर ही दवाएं बिकती रहेंगी। रसायन और उर्वरक पर संसद की स्थायी समिति के एक अध्ययन में पता चला कि दवा कंपनियां बार-बार दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी करके नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। इसका मतलब है कि सरकार ने जितना दाम बढ़ाने को कहा था, उससे ज्यादा दाम बढ़ा रहे थे।

एनपीपीए को दवा कंपनियों द्वारा उल्लंघन के 307 मामले मिले हैं। एनपीपीए, ड्रग (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013 के मुताबिक दवाओं की अधिकतम कीमतें तय करती हैं। कोई भी कंपनी सरकार द्वारा तय की गई कीमत से ज्यादा पर दवाई नहीं बेच सकती। हाल ही में रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा था कि राष्ट्रीय आवश्यक दवाओं की सूची, 2022 में सूचीबद्ध दवाओं की कीमतों में कमी के कारण मरीजों को लाभग 3,788 करोड़ रुपये की सालाना बचत हुई।

ग्लोबल वार्मिंग के चलते अब सौर ऊर्जा से चलने वाले फिज में सुरक्षित रखेंगे टीके



नई दिल्ली। जलवायु परिवर्तन के चलते पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग का सामना कर रही है, जिससे भारत भी अछूता नहीं है। जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन प्रभावों से बचने के लिए केंद्र सरकार ने अनोखी पहल शुरू की है, जिसके तहत देश के सभी राज्य टीका सुरक्षित रखने के लिए सौर ऊर्जा चालित फिजों को स्थापित कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

(एनआईएचएफडब्ल्यू) के निदेशक डॉ. धीरज शाह ने बताया कि 2015 में केंद्र ने राष्ट्रीय कोल्ड चेन एवं टीका प्रबंधन संसाधन केंद्र शुरू किया जो अब देश के सभी जिलों में कोल्ड चेन तकनीशियनों को प्रशिक्षण दे रहा है ताकि इनमें आने वाली तकनीकी खामियों को स्थानीय स्तर पर ही ठीक किया जा सके। शाह ने कहा कि पुरानी तकनीक पर आधारित रेफ्रिजरेटर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देते हैं। इन प्रभावों से बचने के लिए देश के सभी राज्यों में सौर ऊर्जा से चलने वाले रेफ्रिजरेटर स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें -20 से आठ डिग्री सेल्सियस तापमान पर टीकों को सुरक्षित रखा जा सकता है।

नई व्हीकल स्क्रेप पॉलिसी से देश में गाड़ी की सर्विसिंग होगी 30 फीसदी तक सस्ती



नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार की नई व्हीकल स्क्रेप पॉलिसी का सही तरीके से क्रियान्वयन होने पर वाहनों के कलपुर्जों (स्पेयर पार्ट्स) की कीमतों में 30 प्रतिशत तक कमी आ सकती है। इससे गाड़ियों की रिपेयरिंग लागत में भी बड़ी राहत मिल सकती है, और ग्राहकों को कम कीमत पर बेहतर वाहन सेवाएं मिल सकती हैं। गडकरी ने यह भी कहा कि इस कदम का फायदा

वाहन निर्माता कंपनियों को भी होगा, क्योंकि वे सस्ते स्पेयर पार्ट्स का उपयोग करके अपनी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग लागत को कम कर सकेंगी। इससे ग्राहकों को सस्ती कीमतों पर गाड़ियों की रिपेयरिंग सेवाएं मिलेंगी, और कुल मिलाकर वाहन मालिकों की खर्च में कमी आएगी। नितिन गडकरी के अनुसार, अगर व्हीकल स्क्रेप पॉलिसी का पूरी तरह से उपयोग किया जाता है, तो वाहनों की कीमतों में भी कमी हो सकती है। इससे ग्राहक अच्छे और सस्ती गाड़ियां खरीद सकेंगे। गडकरी ने इस मौके पर यह भी बताया कि अगले छह महीनों में देश में इलेक्ट्रिक और पेट्रोल गाड़ियों की कीमतें लगभग समान हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए काम कर रही है, और इससे ईवी की मांग में इजाफा होगा।

देश के जलाशयों का जलस्तर 45% तक गिरा, नदियां भी आधी खाली

नई दिल्ली। मार्च गुजरा भी नहीं कि देश के प्रमुख जलाशयों का जल स्तर तेजी से घटने लगा है। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की रिपोर्ट के अनुसार, देश के ज्यादातर प्रमुख जलाशयों का जलस्तर उनकी कुल क्षमता का 45 फीसदी तक कम हो गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने मार्च से मई के बीच झुलसा देने वाली गर्मी के दिनों की अवधि सामान्य से अधिक रहने की भविष्यवाणी की है। ऐसे में परेशानियां बढ़ने की आशंका है। ये जलाशय सिंचाई के साथ ग्रामीण और शहरी घरेलू जल आपूर्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक हैं। हालांकि, बढ़ते तापमान के साथ इन बहुमूल्य जल संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। सीडब्ल्यूसी के अनुसार, देश के 155 प्रमुख जलाशयों में फिलहाल 8,070 करोड़ क्यूबिक मीटर (बीसीएम) पानी बचा है, जबकि इनकी कुल क्षमता 18,080 करोड़ क्यूबिक मीटर है। इस समय उत्तरी क्षेत्र के जलाशयों का जल स्तर

उनकी कुल क्षमता का सिर्फ 25 फीसदी रह गया है। इनमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के 11 जलाशय हैं। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के जलाशयों में सामान्य से क्रमशः 36 और 45 फीसदी कम पानी है। इसी तरह पश्चिमी क्षेत्र के जलाशयों का जलस्तर उनकी क्षमता का 55%, मध्य क्षेत्र में 49 और पूर्वी क्षेत्र में 44 फीसदी है। देश के कई हिस्सों में पहले ही तापमान सामान्य से बहुत अधिक है और मानसून आने में अभी दो महीने से ज्यादा का समय है। ऐसे में जलाशयों का घटता जलस्तर रबी और खरीफ के बीच उगाई जाने वाली फसलों पर असर डाल सकता है। देश की 20 नदी घाटियों में से 14 में मौजूदा जल भंडार उनकी क्षमता के मुकाबले आधे से भी कम है। इन नदी बेसिनों में से गंगा अपनी सक्रिय क्षमता के मुकाबले मात्र 50 फीसदी पर है, जबकि गोदावरी में 48, नर्मदा में 47 और कृष्णा में सिर्फ 34 फीसदी पानी ही शेष बचा है।

हुरुन रिच लिस्ट, मुकेश अंबानी देश में सबसे अमीर, गौतम अडानी दूसरे नंबर पर

नई दिल्ली। बिजनेस की दुनिया में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भारत के सबसे अमीर शख्स का खिताब बरकरार रखा है। अंबानी परिवार के पास 8.6 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति है। दूसरे नंबर पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी हैं। वे भारत के सबसे बड़े वेल्थ गेनर हैं। उनकी नेटवर्थ में बढ़ोतरी हुई है। एचसीएल की रोशनी नाडार तीसरे नंबर पर हैं। वे भारत के टॉप 10 सबसे अमीर व्यक्तियों में इकलौती महिला हैं। हाल ही में एचसीएल के फाउंडर शिव नाडार ने गंगा अपनी सक्रिय क्षमता के मुकाबले मात्र 50 फीसदी पर है, जबकि गोदावरी में 48, नर्मदा में 47 और कृष्णा में सिर्फ 34 फीसदी पानी ही शेष बचा है।



के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। उनकी संपत्ति में 82% की बढ़ोतरी हुई है। अब उनके पास कुल 420 बिलियन डॉलर संपत्ति है। इस बीच आईटी कंपनी एचसीएल की रोशनी नादर दुनिया की पांचवीं सबसे अमीर महिला बन गई हैं। उनके पास 3.5 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति है। रोशनी नादर पहली भारतीय महिला हैं जो दुनिया की टॉप 10 महिलाओं में शामिल हुई हैं। चौथे स्थान पर सन फार्मा के दिल्ली सांघवी सन फार्मा के दिल्ली सांघवी की संपत्ति में 21% की बढ़ोतरी हुई है।

अब उनके पास 2.5 लाख करोड़ रुपए हैं और वे इस लिस्ट में चौथे स्थान पर आ गए हैं। विप्रो के अजीम प्रेमजी 2.2 लाख करोड़ रुपए के साथ पांचवें, कुमार मंगलम बिड़ला 2 लाख करोड़ रुपये के साथ छठे नंबर पर हैं। साइरस पूनावाला 2 लाख करोड़ रुपये की नेटवर्थ के साथ संयुक्त छठे नंबर पर हैं। पिछले एक साल में उनकी नेटवर्थ में 8 फीसदी गिरावट आई है। मुंबई में सबसे ज्यादा अरबपति बजाज ऑटो के बाले नीरज बजाज 1.6 लाख करोड़ रुपये के साथ आठवें नंबर पर हैं जबकि रवि जयपुरिया और राधाकिशन दमाना 1.4 लाख करोड़ रुपये के साथ संयुक्त रूप से नौवें नंबर पर हैं। मुंबई में सबसे ज्यादा अरबपति हैं। टॉप 10 में से पांच अरबपति मुंबई से हैं। नई दिल्ली में दो अरबपति हैं। बंगलुरु, अहमदाबाद और पुणे में एक-एक अरबपति हैं।

हिमस्खलन से होने वाली मौतों के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर

नई दिल्ली। हिमस्खलन से होने वाली मौतों के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है, जबकि अफगानिस्तान इस सूची में सबसे ऊपर है। कोलोराडो के पहाड़ी क्षेत्रों में भी हर साल हजारों हिमस्खलन होते हैं जो स्कीयर, स्नोबोर्डर्स, हाइकर्स और स्नोमोबिलर्स के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। वहां हर साल औसतन 25 से 30 लोग अपनी जान गंवाते हैं। क्लाइमेट चेंज ओवर द हिमालय नामक अध्ययन के अनुसार, 1951 से 2018 के बीच भारत के हिमालयी क्षेत्रों में तापमान वृद्धि मैदानी इलाकों की तुलना में अधिक तेज रही है। खासतौर पर 4,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यह वृद्धि 0.5 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक तक देखी गई है। इस बढ़ते तापमान के कारण हिमालय में अधिक हिमस्खलन हो रहे हैं, जिससे जान-माल का भारी नुकसान हो रहा है और स्थानीय लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है। हिमालय में 1972 से 2022

के बीच हर साल औसतन 62 लोगों की जान गई, जिससे कुल 3,100 से अधिक मौतें दर्ज की गईं। इनमें सबसे अधिक 1,057 मौतें अफगानिस्तान में हुईं, जबकि भारत 952 मौतों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। नेपाल, भूटान और पाकिस्तान में भी हिमस्खलन के कारण कई जानें गईं। उत्तराखंड में हिमस्खलन की दृष्टि से सबसे संवेदनशील क्षेत्र उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले हैं। खासकर 3000 मीटर से ऊपर के क्षेत्र हिमस्खलन के लिहाज से अत्यधिक संवेदनशील हैं। मीणा-बदरीनाथ क्षेत्र समुद्र तल से 3100-3300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह हिमस्खलन की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। जोशीमठ मलारी-सुमना और बदरीनाथ घाटी यानी पांडुकेश्वर-लामबगढ़-हनुमान चाली में कई मजदूर झोपड़ियों में रह रहे हैं, जो अधिकतर भूस्खलन और हिमस्खलन की संवेदनशील जगहों पर स्थित हैं।

1 अप्रैल से सरकारी जमीन की कीमतों में होगा भारी इजाफा

मिटी चीफ इंदौर। इंदौर। 1 अप्रैल से लागू होने वाली नई गाइडलाइन के तहत स्टाम्प ड्यूटी में 10 प्रतिशत से लेकर 274 प्रतिशत तक की भारी बढ़ोतरी की जा रही है। इससे जुड़े सभी प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी के लिए आज भोपाल मुख्यालय भेजा जाएगा। पंजीयन विभाग ने इस प्रस्तावित गाइडलाइन पर प्राप्त 138 दावे-आपत्तियों का समाधान कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप 70 नई कॉलोनियों को शामिल किया गया है, साथ ही कई गांवों की गाइडलाइन दरों में भी इजाफा किया गया है। अब कुल मिलाकर 4972 स्थानों पर



सरकारी जमीन की कीमतें बढ़ जाएंगी और इन्हीं के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी वसूली की जाएगी। इकोनॉमिक कॉरिडोर और अन्य परियोजनाएं गाइडलाइन में प्राधिकरण की

प्रस्तावित टीपीएस योजनाओं में शामिल जमीनों के अलावा इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर तथा अन्य प्रमुख परियोजनाओं से जुड़ी जमीनों को भी शामिल किया गया है। स्टाम्प ड्यूटी से शासन को सबसे अधिक राजस्व इंदौर से प्राप्त होता है। चालू वित्त वर्ष में शासन ने 3200 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें से अब तक लगभग 2300 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। शेष सप्ताह में अधिक से अधिक रजिस्ट्रियों की संभावना है, जिसके चलते अंतिम 3-4 दिनों में स्लॉटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

जनप्रतिनिधियों और किसानों की मांग पर बढ़ी दरें वरिष्ठ जिला पंजीयक अमरेश नायडू के अनुसार, काली बिल्लौद के किसानों ने मांग की थी कि 2016 से गाइडलाइन नहीं बढ़ाई गई है, इसलिए उनकी बात को मान्य किया गया। इसी तरह विधायक मधु वर्मा द्वारा तिल्लौर बुजुर्ग की गाइडलाइन बढ़ाने की अनुरासा की गई, जिसे स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं, जीतू पटवारी और मुकेश पटवारी ने कैलोदकतान और वतनखेड़ी गांवों की गाइडलाइन बढ़ाने की मांग की थी, जिसे आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है।

कुल स्थानों की संख्या पहुंची 4972 प्राप्त प्रस्तावों में कुछ अन्य गांवों के साथ-साथ 70 नई कॉलोनियों को भी गाइडलाइन में सम्मिलित करने का सुझाव था, जिसे मंजूरी दे दी गई है। इसके परिणामस्वरूप अब कुल 310 नई कॉलोनियां गाइडलाइन में शामिल हो चुकी हैं। इस प्रकार 1 अप्रैल से कुल 4972 स्थानों पर जमीन की सरकारी कीमतों में वृद्धि प्रभावी होगी। इसके आधार पर स्टाम्प ड्यूटी का निर्धारण किया जाएगा, जिससे शासन को राजस्व संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है।

भावना हत्याकांड के तीनों आरोपी गिरफ्तार, मुकुल से चली थी गोली

मिटी चीफ इंदौर। इंदौर। इंदौर में हुए भावना हत्याकांड की गुथी पुलिस ने सुलझा ली है। इस हत्याकांड के आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस ने इन पर 10-10 हजार का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस ने आरोपी आशु यादव, मुकुल और स्वास्तिका को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया है, ताकि वे विदेश न भाग सकें। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भावना को मुकुल के हाथ से चली गोली लगी थी। जो उसकी मौत की वजह बनी। पुलिस ने आरोपियों को दतिया से पकड़ा है। आरोपी इंदौर में भावना को बांबे अस्पताल में भर्ती कराने के बाद भाग गए थे। पुलिस के अनुसार आरोपी बस में बैठकर इंदौर से भोपाल गए। वहां पर विख्यात पाठक के घर पर रुके थे। इस वजह से उसे भी केस में आरोपी बनाया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी भोपाल से दतिया गए। अफसरों ने ग्वालियर और दतिया में उनके परिजनों से भी पूछताछ की, लेकिन आरोपियों ने अपने परिजनों से भी संपर्क नहीं किया है। इंदौर के महालक्ष्मी नगर में विख्यात पाठक ने रेंट एग्रीमेंट कराया था। वह आशु का दोस्त है।



हत्या के चार दिन बाद गिरफ्तारी पुलिस के अनुसार पार्टी के समय भावना घर जाने के लिए कह रही थी। उसी समय हादसा हुआ। मुकुल के हाथ से चली गोली भावना की आंख में लगी। इसके बाद आरोपी उसे बांबे अस्पताल लेकर गए थे। भावना को भर्ती कराने के बाद वे वहां से भाग गए थे। उन्होंने अपनी कार निपानिया क्षेत्र में छोड़ दी थी। हत्या के चार दिन बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भावना सिंह की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर ग्वालियर में कैंडल

मार्च भी निकाला गया था। भावना ग्वालियर की निवासी थी। **नेपाल भागने की तैयारी में थे आरोपी** पुलिस को जानकारी मिली थी आरोपी आशु अपने दोस्तों के साथ हिमाचल प्रदेश के कसौली में छुपा है। पुलिस की टीम ने वहां छपा मारा, लेकिन तब तक वह वहां से भाग चुके थे। यह पता चला था कि वे ग्वालियर, झांसी, कानपुर के रास्ते नेपाल भागने की तैयारी में थे। वे दतिया में रुके थे। वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया **सट्टे का केस भी दर्ज** आरोपी ऑनलाइन सट्टा एप का काम भी करते थे। जिस प्लैट में भावना की हत्या हुई थी। वहां से पुलिस ने 20 से ज्यादा मोबाइल, लैपटॉप और 50 से अधिक एटीएम कार्ड 60 बैंकों की पासबुक भी मिली थी। इंदौर से वे देशभर में सट्टे का कारोबार करते थे। पुलिस ने हत्या के अलावा सट्टेबाजी का केस भी दर्ज

कृषि कॉलेज के डीन के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग को लेकर प्रदर्शन

मिटी चीफ इंदौर। इंदौर। शासकीय कृषि कॉलेज के बाहर बुधवार को प्रदर्शन करने पर तिलक नगर पुलिस ने प्रदर्शनकारी राधे जाट के खिलाफ केस दर्ज किया है। गुरुवार को कॉलेज के स्टूडेंट्स ने राधे जाट के नेतृत्व में कृषि कॉलेज से तिलक नगर थाने पहुंचे। यहां उन्होंने कॉलेज के डीन के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। स्टूडेंट्स पैदल मार्च निकालकर कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरना देने वाले थे, लेकिन थाने पर पुलिस के आश्वासन के बाद उन्होंने पैदल मार्च और कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरना देना निरस्त कर दिया। दरअसल, कॉलेज के स्टूडेंट्स, डीन को हटाने की मांग कर रहे हैं। बुधवार को भी उन्होंने कॉलेज गेट पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। स्टूडेंट्स का कहना है कि कॉलेज के डीन प्रो. भरत सिंह को हटाया जाए। कुछ समय पहले उनकी शिकायत



कुलपति से की गई थी, तब से ही वे स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ने डीन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। डीन का कहना है कि हाल ही में रैगिंग को लेकर जो कार्रवाई हुई है, उसी को लेकर उन्हें टारगेट किया जा रहा है। इधर, बुधवार को स्टूडेंट्स के प्रदर्शन में राधे जाट भी शामिल हुए। इससे पहले, राधे जाट कुछ माह पहले एमपीपीएससी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन में भी शामिल हो चुके हैं। कॉलेज गेट पर प्रदर्शन की सूचना मिलने पर पुलिस मौके

पर पहुंची। स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी। तिलक नगर पुलिस ने प्रदर्शन करने के मामले में राधे जाट के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। राधे जाट का कहना है कि स्टूडेंट्स का ध्यान भटकाने के लिए यह कार्रवाई की गई है। उल्लेखनीय है कि एमपीपीएससी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने सहित अन्य मामलों में राधे जाट पर पहले भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। राधे जाट के नेतृत्व में कृषि कॉलेज से स्टूडेंट्स तिलक नगर थाने पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने कॉलेज के डीन के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग करते हुए ज्ञापन भी सौंपा। पुलिस ने स्टूडेंट्स को मामले में जांच का आश्वासन दिया। इस आश्वासन के बाद उन्होंने कृषि कॉलेज से कलेक्टर ऑफिस तक पैदल मार्च निकालना और कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरना देना निरस्त कर दिया है। फिलहाल स्टूडेंट्स कॉलेज के गेट पर ही बैठे हैं।

सड़कों पर दौड़ रहे बिना नंबर के टैंकर, पानी की हो रही भारी बर्बादी

मिटी चीफ इंदौर। इंदौर। शहर में पानी की किल्लत बढ़ गई है। नगर निगम द्वारा हवाियों तक पानी पहुंचाने के लिए टैंकरों की व्यवस्था की जाती है, लेकिन इन टैंकरों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। नगर निगम में अटैच कई टैंकरों के पास नंबर प्लेट तक नहीं हैं और वे बिना किसी नियम-कायदे के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इन टैंकरों की तेज रफ्तार से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। इतना ही नहीं, इनमें से कई टैंकर जर्जर हालत में हैं, जिनसे लगातार पानी रिसता रहता है,



जिससे बड़ी मात्रा में पानी बर्बाद हो रहा है। शहर के कई जौन में ऐसे टैंकर अटैच किए गए हैं, जिनकी नंबर प्लेट गायब है और उनकी

नगर निगम के अधिकारी इस गंभीर समस्या की अनदेखी कर रहे हैं। पानी की सप्लाई के दौरान भारी मात्रा में पानी बर्बाद हो रहा है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। यह पानी जहां लोगों की जरूरतें पूरी कर सकता था, वहीं अब व्यर्थ में बहकर नालियों में चला जाता है। **नेताओं के दबाव में हो रही टैंकर अटैचमेंट प्रक्रिया** सूत्रों के अनुसार, नगर निगम में टैंकरों को अटैच करने की प्रक्रिया में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ गया है। नेताओं द्वारा अपने प्रभाव का

इस्तेमाल कर टैंकरों को निगम में शामिल करवाया जा रहा है, चाहे वे नियमों के अनुरूप हों या नहीं। नगर निगम के प्रत्येक जोनल कार्यालय पर नर्मदा प्रोजेक्ट अधिकारियों को नेताओं की इच्छानुसार टैंकर अटैच करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। कई टैंकर तो ऐसे हैं जो सालभर से निगम में जुड़े हुए हैं और पानी सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश की स्थिति बेहद खराब है। इसके बावजूद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी नेताओं के दबाव के कारण इन टैंकरों पर कोई

कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आम जनता पानी की समस्या से जूझ रही है। बिना नंबर और जर्जर टैंकरों का सबसे बड़ा खतरा उनकी तेज रफ्तार है। निगम से अनुबंधित टैंकरों के चालक लापरवाहीपूर्वक टैंकर चलाते हैं, जिससे सड़क पर दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। निगम में जुड़े हुए हैं और पानी सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश की स्थिति बेहद खराब है। इसके बावजूद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी नेताओं के दबाव के कारण इन टैंकरों पर कोई

मॉल में धोती पहनने पर हुआ विवाद तो युवाओं ने किया विरोध प्रदर्शन

इंदौर। इंदौर के एक मॉल में धोती पहनने पर विवाद हो गया तो बाद में बड़ी संख्या में युवा मॉल में पहुंचे और धोती पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। इन्होंने भारतीय परिधान पहनने के पक्ष में नारे भी लगाए। दरअसल देवास के विजय सिंह ठाकुर नाम के जिम संचालक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि इंदौर के एक मॉल में वे धोती पहनकर गए तो वहां के सुरक्षाकर्मियों ने उनसे विवाद किया। इसके बाद जब यह वीडियो वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर भारतीय परिधानों के प्रति लोगों की भावनाएं उमड़ गईं। रविवार को विजय सिंह ठाकुर अपने दोस्तों के साथ मॉल गए थे। उन्होंने उस समय हुए विवाद

का वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इसके बाद फिर वे अपने दोस्तों के साथ मॉल में गए और धोती पहनकर पूरे मॉल में घूमे। उस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में युवा थे जो सभी धोती पहने हुए थे। सभी ने सोशल मीडिया के लिए खूब रीलस बनाईं और कहा कि भारतीय परिधानों पर हम सभी को गर्व होना चाहिए। विजय सिंह ठाकुर का यह वीडियो एक मिलियन से अधिक लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसे 70 हजार लोगों ने लाइक किया है। इस मामले में मॉल प्रबंधन से बातचीत करने के लिए कई बार फोन लगाया गया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया।

3 अप्रैल को पेश होगा नगर निगम का आठ हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट

मिटी चीफ इंदौर। इंदौर। इंदौर नगर निगम 3 अप्रैल को बजट पेश कर रहा है। इस साल कोई नया टैक्स तो नहीं लगाया, लेकिन पिछले बजट में प्रॉपर्टी टैक्स के जो रेट जोन बदले हैं। उसे इस वित्तिय वर्ष में लागू किया जाएगा। इस साल मास्टर प्लान की सड़क और नर्मदा के चौथे चरण पर नगर निगम का फोकस रहेगा। बजट को लेकर बैठकों का दौर भी जारी है इस साल का बजट आठ हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का होगा। सबसे ज्यादा खर्च जनकार्य विभाग के लिए रखा जाएगा। सिंहस्थ को देखते हुए भी नगर निगम शहर में काम करेगा। 3 अप्रैल को बजट पेश किया जाएगा। उसके बाद 4 अप्रैल को बजट पर चर्चा होगी और उसे बहुमत के आधार पर पारित किया जाएगा।

नगर निगम सीमा में जुड़े 29 गांवों के लिए भी निगम बड़ा पैकेज देगा। इन क्षेत्रों में 300 करोड़ से ज्यादा के काम होना है। नगर निगम टैक्स के माध्यम से अपनी आय बढ़ाएगा। नए रेट जोन से निगम को हर साल 11 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी। इसके अलावा मनोरंजन कर से भी पांच करोड़ से ज्यादा की कमाई नगर निगम को होगी। जीआरआई सर्वे के आधार पर भी संपत्तिकर बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। शहर में नए निर्माण हो चुके हैं, लेकिन शहरवासी वर्षों पुरानी स्व निर्धारण कर प्रणाली के आधार पर ही टैक्स देते हैं। सर्वे के बाद टैक्स में भी बढ़ौतरी होगी। नगर पालिका निगम परिषद का बजट सम्मेलन 3 अप्रैल को सुबह 11 बजे श्री अटल बिहारी वाजपेयी

परिषद सभागृह, अटल सदन, नगर निगम मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में महापौर पुष्पमित्र भार्गव नगर निगम का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही बजट सम्मेलन में अन्य विषयों पर भी चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि इस बार जनकार्य विभाग को 2,000 करोड़ रुपए का बजट मिलेगा, जिससे शहर के विकास कार्यों में तेजी आएगी। मनोरंजन कर पर पिछले साल से सख्ती बढ़ाई गई है, जिससे इस साल 5 से 10 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। अनुमान है कि बढ़े हुए संपत्तिकर से 11.83 करोड़ रुपए अधिक जमा होगा। जलकर से 31 करोड़ रुपए और अन्य मदों से 6 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी।

पानी की हो रही भारी बर्बादी

कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आम जनता पानी की समस्या से जूझ रही है। बिना नंबर और जर्जर टैंकरों का सबसे बड़ा खतरा उनकी तेज रफ्तार है। निगम से अनुबंधित टैंकरों के चालक लापरवाहीपूर्वक टैंकर चलाते हैं, जिससे सड़क पर दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। निगम में जुड़े हुए हैं और पानी सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश की स्थिति बेहद खराब है। इसके बावजूद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी नेताओं के दबाव के कारण इन टैंकरों पर कोई

खान से सवाल किया गया, तो उन्होंने इसे नर्मदा प्रोजेक्ट अधिकारियों की जिम्मेदारी बताकर पल्ला झाड़ लिया। इसी तरह, जोन 3 के अंतर्गत सिंघ, जोन 6 के लोकेश शर्मा और जोन 14 के सालकराम शितोले ने भी यही बयान दिया कि टैंकरों की देखरेख नर्मदा प्रोजेक्ट के अधिकारियों द्वारा की जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि नगर निगम में टैंकरों की व्यवस्था पूरी तरह से अव्यवस्थित और लापरवाही से भरी हुई है, जिससे पानी की बर्बादी और दुर्घटनाओं की संभावना लगातार बनी हुई है।

कांग्रेस विधायक द्वारा साधु-संतों की तुलना सांड से करने पर बवाल

विधायक ने वीडियो जारी कर दी सफाई

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक द्वारा साधु संतों की तुलना सांड से करने पर सियासी जंग छिड़ गई है। जहां प्रदेश भर के साधु संत इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं भाजपा के नेता कांग्रेस को लगातार घेर रहे हैं। बवाल मचने के बाद विधायक डॉ राजेंद्र सिंह ने अपने बयान पर सफाई दी है। सहकारिता और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने हमला बोलते हुए कांग्रेस नेतृत्व से विधायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले में मंचे बवाल के बाद कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि मेरी बात की लोगों ने अलग-अलग



व्याख्या की है। साधु संतों का काम करना नहीं है। साधु संतों को महामंडलेश्वर का काम किसी पार्टी का किसी दल से सहानुभूति हो सकती है,

लेकिन प्रचार करना ठीक नहीं है। हम लोग सभी धर्म को मानने वाले लोग हैं।

कांग्रेस विधायक ने बताया था सांड गौरतलब है कि प्रदेश के पूर्व मंत्री व अमरपटन से कांग्रेस विधायक डॉ. राजेंद्र कुमार सिंह ने साधु-संतों को लेकर विवादित बयान दिया था। सतना में आयोजित कार्यक्रमों सम्मेलन में उन्होंने साधु-संतों और महामंडलेश्वरों सांड बताया था। राजेंद्र कुमार ने कहा था कि संयोग ऐसा कि राम मंदिर आ गया, उधर महाकुंभ आ गया। कितना प्रचार हुआ, मैंने तो गणित लगाया, 10-12 करोड़ से ज्यादा लोग नहीं गए। उन्होंने आगे कहा था कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, इंजीनियर

हूँ। 60 करोड़ लोग, वाट्सएप यूनिवर्सिटी ने लोगों के दिमाग में भर दिया। फिर इन्होंने साधु-संत, संन्यासी, बाबा बैरागी और महामंडलेश्वरों को छोड़ दिया जनता के बीच, जाओ हिंदुत्व की बात करो, भाजपा का प्रचार करो, सनातन की बात करो और ये सांड, चर रहे हैं दूसरों का खेत। **क्या कांग्रेस हिंदू समाज को समाप्त करने की साजिश** कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह द्वारा साधु-संतों की तुलना सांडों से करने वाले विवादित बयान पर मध्यप्रदेश के सहकारिता और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने हमला बोलते हुए कांग्रेस नेतृत्व से विधायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई

की मांग की है और यह भी कहा कि यदि कांग्रेस इस मामले में कोई कदम नहीं उठाती है, तो इसे पार्टी का आधिकारिक बयान माना जाएगा। **इससे बड़ा कुकृत्य और कुछ नहीं हो सकता** मंत्री सारंग ने विधायक राजेंद्र सिंह के बयान की निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस हिंदू देवी-देवताओं और सनातन धर्म का लगातार अपमान कर रही है। अब तो हद हो गई, हमारे पूज्य साधु-संतों की तुलना सांडों से की जा रही है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि यह टिप्पणी उस मंच से की गई जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मौजूद थे, यह दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही लेकिन इससे बड़ा कुकृत्य और कुछ नहीं हो सकता।

भोपाल जिला पंचायत की चार महीने बाद हुई बैठक में जमकर हंगामा

पानी, सड़क, बिजली के मुद्दे पर दिखी नाराजगी

भोपाल। जिला पंचायत की बैठक चार महीने बाद गुरुवार को आयोजित की गई। इस बैठक सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। सभी सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की परेशानियों को लेकर अधिकारियों को निशाने पर लिया। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, पीएचई, कृषि, पीडब्ल्यूडी, आदिम जाति, वन, महिला और बाल विकास समेत 15 विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। सदस्यों ने सबसे ज्यादा पीएचसी विभाग और जल निगम के अधिकारियों पर नाराजगी जताई। जल जीवन मिशन के कार्य में हो रही देरी को लेकर अधिकारियों और सदस्यों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। इससे पहले सामान्य प्रशासन समिति की मीटिंग भी हुई, जिसमें प्रतिनिधियों को एंटी नहीं दी गई। जिला पंचायत की बैठक में अध्यक्ष रामकुंवर गुर्जर, उपाध्यक्ष जाट, सदस्य मेहर, विक्रम भालेराव, रश्मि भार्गव, बिजिया राजोरिया, चंद्रेश राजपूत, गंगाबाई मालवीय, रामकुंवर हाड़ा, जनपद अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत, विधायक प्रतिनिधि दीपक गुर्जर, सीईओ तिवारी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। **70वां गांव में नहीं पहुंचा जल जीवन मिशन का पानी** इस बैठक में सबसे ज्यादा नाराजगी जल जीवन मिशन में हो रही देरी को लेकर सदस्यों ने जताई है।



उपाध्यक्ष मोहन सिंह जाट ने कहा कि 70 फ्रीसदी गांव में अभी तक जल जीवन मिशन से पानी की सप्लाई नहीं हो पाई है। उन्होंने पीएचई के इंजीनियर संजय सक्सेना पर जमकर नाराजगी जाहिर की। इस दौरान उन्होंने खड़े होकर संजय सक्सेना को पास बुलाया और लगा की स्थिति बिगड़ जाएगी लेकिन सदस्यों ने मामले को संभाल लिया। बैठक में गांव में पानी, सड़क को लेकर सदस्य मेहर, जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत में भी विरोध जताया। कहा कि अधिकारी सुनते नहीं हैं। हर बार ऐसा ही रवैया रहा है। ऐसा ही रहा तो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। **पुरे गांव की काट रहे बिजली** बैठक में बिजली कंपनी के ईई पंकज यादव पर फंदा जनपद

अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत में जमि का नाराजगी जताई। गांवों में बकाया राशि का हवाला देकर पूरे गांव की बिजली काटने पर नाराजगी जताते हुए राजपूत ने कहा कि आप यादव होने का फायदा उठा रहे हैं। आप पंकज बाद में और यादव पहले कहते हैं। आरोपों पर कार्यपालन यंत्री पंकज यादव ने कहा कि नियमानुसार ही कनेक्शन काटने का काम होता है। सदस्य विक्रम भालेराव के काम नहीं होने पर आपत्ति जताई और संबंधित अधिकारी पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि गांवों में हैंडपंप बंद हो रहे हैं और अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि हम विरोध कर रहे हैं। काम नहीं होने से हमारा गांवों में जाना मुश्किल हो गया है। लोग हमारा विरोध कर रहे हैं।

भोपाल सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर तिवारी ने स्वास्थ्य विभाग के बारे में जानकारी देना शुरू की तो सदस्य मेहर ने बैरसिया सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर की कमी होने की बात कही। सीएमएचओ ने भी डॉक्टर की कमी पर सहमति जताते हुए कहा कि सभी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है। जिला अस्पताल में एक भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। सदस्य मेहर ने यहां पर एक महिला और एक पुरुष डॉक्टर की नियुक्ति नियमित रूप से करने को कहा। सीएमएचओ ने स्वास्थ्य केंद्रों पर सभी व्यवस्था दुर्बल होने की बात कही तो सदस्य चंद्रेश राजपूत ने कहा कि अब हम आपके लिए निगरानी का काम भी करें? ये तो आपको ही करना है। सदस्य भालेराव ने आयुष्मान के इलाज के दौरान अस्पतालों में मरीज को होने वाली परेशानियों के बारे में बताया। बैठक में सरकारी स्कूलों की जर्जर बिल्डिंग का मुद्दा उठाया। वहीं, उपाध्यक्ष जाट ने शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर कोई कार्यवाही नहीं होने पर नाराजगी जताई। सदस्य भार्गव, भालेराव ने भी शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी को लेकर समस्या बताई। उपाध्यक्ष जाट ने कहा कि अधिकारी ठेकेदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों की कुछ भी सुन रहे हैं।

बीजेपी विधायक ने नवरात्रि में मांस दुकानों को बंद रखने की मांग

कांग्रेस नेता का भाजपा पर पलटवार

सिटी चीफ भोपाल। भोपाल। मध्य प्रदेश में नवरात्रि के दौरान नौ दिनों तक मांस, मछली और चिकन की दुकानों को बंद करने की मांग जोर पकड़ रही है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने नवरात्रि के दौरान मांस दुकानों को बंद करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए नवरात्रि के दौरान मांस दुकानों को बंद करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि गंगा-जमुनी तहजीब की बात करने वाले दलों को

हिंदू त्योहारों के महत्व को भी समझना चाहिए। शर्मा ने सवाल उठाया कि गंगा-जमुनी तहजीब केवल हिंदुओं पर ही क्यों लागू होती है? अगर मुस्लिम समुदाय हिंदू त्योहारों का सम्मान करेगा, तो हिंदू भी उनके पर्वों का सम्मान करेंगे। इस मुद्दे को लेकर भारत रक्षा मंच ने कलेक्टर कोशलेंद्र विक्रम सिंह को पत्र भेजा है, जिसमें नवरात्रि के नौ दिनों तक मांस दुकानों को बंद करने की अपील की गई है। मंच का कहना है कि खुले में लटक

मांस से नवरात्रि के दौरान हिंदू श्रद्धालुओं और उपवास करने वालों की भावनाएं आहत होती हैं। इसी मांग का समर्थन संस्कृति बचाओ मंच के संयोजक चंद्रशेखर तिवारी ने भी किया है, जिन्होंने कहा कि नवरात्रि के पूरे नौ दिनों तक मांस और मटन की दुकानों को बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि यह समय माता की पूजा और उपासना का होता है। **कांग्रेस का भाजपा पर माहौल खराब करने का आरोप** वहीं, इस मुद्दे पर कांग्रेस के

मुख्य प्रवक्ता अब्बास हफीज ने भाजपा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानों से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। हफीज ने कहा कि भोपाल गंगा-जमुनी तहजीब का शहर है, जहां हर धर्म के लोग एक-दूसरे के त्योहारों का सम्मान करते हैं। बता दें कि चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू हो रही है, जिसे हिंदू समाज अपना पवित्र त्योहार मानता है। इस दौरान नौ दिन माता की पूजा और उपासना की जाती है।

मऊगंज के शहीद गौतम के परिवार को 1 करोड़ का चेक

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर मऊगंज जिले के स्व. रामचरण गौतम के परिवार को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के अंतर्गत एक करोड़ रुपये की राशि का चेक प्रदान किया। भारतीय स्टेट बैंक की पुलिस सेलरी पैकेज योजना में पुलिसकर्मियों को दी जाने वाली पूरक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सुविधा के अनुसार परिवार को यह राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शहीद गौतम के पात्र उत्तराधिकारी को

शासकीय सेवा में लेने के निर्देश पुलिस महानिदेशक को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि कर्तव्य निर्वहन के दौरान अपने प्राणों को उत्सर्ग करने वाले पुलिस उपनिरीक्षक रामचरण गौतम की पत्नी पुष्पा गौतम को चेक प्रदान करते हुए कहा कि राज्य शासन ने स्व. गौतम को शहीद का दर्जा देते हुए उनके आश्रितों को एक करोड़ रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की है। ग्राम गडरा जिला मऊगंज में कर्तव्य निर्वहन करते हुए इस माह पुलिस उप निरीक्षक रामचरण

गौतम शहीद हुए। स्व. गौतम के परिवार को बीमा की अनुदान राशि का चेक सौंपे जाने के अवसर पर पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना, सीजीएम एसबीआई म.प्र./छ.ग चंद्रशेखर शर्मा, महाप्रबंधक अजिताभ पाराशर, महाप्रबंधक कुन्दन ज्योति, महाप्रबंधक मनोज कुमार सहित भारतीय स्टेट बैंक के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने स्व. गौतम की धर्मपत्नी पुष्पा और इस अवसर पर उपस्थित स्व. गौतम के पुत्र धीरेंद्र और भतीजे सतीश से चर्चा की।

29 मार्च को भोपाल में कवि सम्मेलन 30 हजार से अधिक श्रोता होंगे शामिल

सिटी चीफ भोपाल।

राजधानी भोपाल में शनिवार को 'कर्मश्री' संस्था द्वारा आयोजित किए जाने वाले अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के रूप में हिंदू नववर्ष का उत्सव भूमधाम से मनाया जाएगा। यह आयोजन 'अदल पथ' पर प्लैटिनम प्लाजा माता मंदिर, तात्या टोपे नगर में रात 8 बजे से शुरू होगा। इस वर्ष यह आयोजन 25वें साल में प्रवेश कर रहा है, और कोविड-19 के समय को छोड़कर यह आयोजन निरंतर होता रहा है। कर्मश्री संस्था के अध्यक्ष और हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने बताया कि हिंदू नववर्ष के अवसर पर यह कवि सम्मेलन हमेशा की तरह भव्य रूप में आयोजित किया जा रहा है। इस

साल के आयोजन में देशभर के मशहूर कवि शामिल होंगे, जिनमें शशिकांत यादव शशि (देवास), पद्मश्री डॉ. सुनील जोगी (नई दिल्ली), डॉ. सुरेंद्र दुबे (रायपुर), कविता तिवारी (लखनऊ), डॉ. अनिल चौबे (वाराणसी) और कई अन्य प्रमुख कवि शिरकत करेंगे। इस कवि सम्मेलन में 30,000 से अधिक श्रोता शामिल होंगे। विधायक शर्मा ने इस आयोजन का महत्व बताते हुए कहा कि इस साल का कवि सम्मेलन 25वां आयोजन है और इसे हर साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, गुड़ी पड़वा और चैती चांद जैसे अवसरों पर आयोजित किया जाता है। इस आयोजन का उद्देश्य पूरे शहर को हिंदू नववर्ष के उल्लास में शामिल

करना है। कार्यक्रम में महिलाओं और बुजुर्गों के लिए विशेष बैठक व्यवस्था की जाएगी और यह व्यवस्था पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगी। विधायक ने भोपालवासियों से अपील की है कि वे इस अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में आकर काव्य रस का आनंद लें और नववर्ष का स्वागत भूमधाम से करें। रामेश्वर शर्मा ने यह भी कहा कि हिंदू नववर्ष का उल्लास देशभर में विभिन्न नामों से मनाया जाता है, जैसे महाराष्ट्र में 'गुड़ी पड़वा' और दक्षिण भारत में 'उगादी'। उन्होंने बताया कि इस दिन से नववर्ष की शुरुआत होती है, और यह भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री आज सिंगल क्लिक से श्रमिक परिवारों को करेंगे राशि का अंतरण

सिटी चीफ भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 28 मार्च को मंत्रालय में संबल योजना में अनुग्रह सहायता के 23 हजार 162 प्रकरणों में 505 करोड़ रुपये सिंगल क्लिक से हितग्राहियों के खातों में अंतरित करेंगे। कार्यक्रम में श्रम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल एवं प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मंत्री एवं स्थानीय जन प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण योजना है। योजना में अनुग्रह सहायता योजना अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपये एवं सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये प्रदान

किए जाते हैं। स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपये एवं आंशिक स्थायी अपंगता पर 1 लाख रुपये तथा अत्येष्टि सहायता के रूप में 5 हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं। संबल योजना में महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता के रूप में 16 हजार रुपये दिए जाते हैं, साथ ही श्रमिकों के बच्चों को महाविद्यालयीन शिक्षा प्रोत्साहन योजना में उच्च शिक्षा के लिए संपूर्ण शिक्षण शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। नीति आयोग की पहल पर प्रदेश के गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी संबल योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाकर इनका पंजीयन प्रारंभ किया गया है। इन्हें भी संबल योजना के अंतर्गत समस्त लाभ प्रदान किए जा रहे हैं।

बिजली बिल वसूली में अचानक सख्ती से किसानों में रोष, सीएम निकालें बीच का रास्ता

पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने दर्ज कराई आपत्ति

सिटी चीफ भोपाल। भोपाल। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रदेश में बिजली की बकाया राशि की वसूली में बरती जा रही अति सख्ती पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा कि बिजली बिल समय पर जमा ना करने वालों में अधिकतर किसान हैं और इनमें भी 90वां छोटे और सीमांत किसान हैं। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रदेश में बिजली की बकाया राशि की वसूली में बरती जा रही अति सख्ती पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने आपत्ति दर्ज की



है। उन्होंने कहा कि बिजली बिल समय पर जमा ना करने वालों में अधिकतर किसान हैं और इनमें भी 90वां छोटे और सीमांत किसान हैं। अजय सिंह ने कहा है कि विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अचानक ही सख्ती किए जाने के कारण किसानों में रोष बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जिन गांवों का ज्यादा बिल बकाया है वहां पर पूरे गांव की बिजली काटी जा रही है। लिहाजा गर्मी के समय गांव में पानी की सप्लाई प्रभावित हो रही है साथ ही गर्मियों की सब्जियां लगाने वाले किसानों की फसल पानी के अभाव में नष्ट होने की

कगार पर है ऐसे में बिजली बिल वसूली में अति सख्ती न की जाकर अधिकारियों को किसानों के प्रति संवेदनशील रख अपनाया जाना चाहिए ताकि आक्रोश के कारण पैदा होने वाली अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। **गरीब किसानों पर जोर जबरदस्ती की अति** उन्होंने कहा कि भू राजस्व संहिता के अंतर्गत सी फार्म और कुर्की करने, बैंक खाते सील करने और खसरो में बकाया राशि की जानकारी दर्ज करने तथा धारा 138 के प्रकरण बनाए जाने जैसी कार्यवाही गरीब किसानों पर जोर

जबरदस्ती की अति है। पहले आपसी बातचीत, समझाईश, ग्राम पंचायत के सहयोग आदि के प्रति संवेदनशील रख वसूली की कार्यवाही की जा सकती है। इसके बाद चेतावनी दी जाए। शुरू से ही सख्ती करने पर किसानों में आक्रोश पैदा होगा। अजय सिंह ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से आग्रह किया है कि वे समस्या की गंभीरता को देखते हुए किसानों और बिजली कंपनी के लिए कोई बीच का रास्ता निकाले ताकि बिजली बिल भी वसूला जाए और किसानों तथा जनता को अकारण परेशानी से बचाया जा सके।

सम्पादकीय

रेप को लेकर असंवेदनशील और अमानवीय नजरिये वाला फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की उस टिप्पणी पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि केवल छाती पकड़ना, पायजामा का नाड़ा खींचना दुष्कर्म के प्रयास का अपराध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि टिप्पणी पूरी तरह असंवेदनशीलता और अमानवीय दृष्टिकोण को दर्शाती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में की गई विवादास्पद टिप्पणियों पर शुरू की गई स्वतः संज्ञान कार्यवाही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, यूपी सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है और फैसला सुनाने वाले न्यायाधीश की ओर से पूरी तरह असंवेदनशीलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि यह फैसले को लिखते हुए अपनाई गई असंवेदनशीलता को दर्शाता है।

विगत 17 मार्च को आया इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला पिछले दिनों पूरे देश में सवालियों के घेरे में था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाकर न्याय की संवेदनशीलता को संबल दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को लेकर महिला संगठनों व बौद्धिक वर्गों में तल्लख प्रतिक्रिया देखी जा रही थी। यहां तक कि महिला संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था। शीर्ष अदालत के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने माना कि फैसला न केवल असंवेदनशील है बल्कि अमानवीय नजरिया भी दर्शाता है। इसके चलते इस फैसले पर रोक लगाना आवश्यक हो जाता है। बेंच ने माना कि फैसला लिखने में संवेदनशीलता की कमी दृष्टिगोचर होती है। कोर्ट का मानना था कि जब फैसला चार माह तक सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया तो यह नहीं कहा जा सकता कि इस पर गंभीर मंथन नहीं हुआ। वहीं शीर्ष अदालत ने इस मसले पर केंद्र व उत्तरप्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया है। उल्लेखनीय है कि सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की निंदा की। दरअसल, विवाद इस बात को लेकर हुआ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पीड़िता किशोरी के स्तनों को छूना व पायजामे की डोरी तोड़ना बलात्कार या बलात्कार की कोशिश नहीं माना जा सकता। उल्लेखनीय है कि यह मामला उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद के पटियाली थाना क्षेत्र में एक किशोरी से जुड़ा था, जिसके बाबत जस्टिस राममनोहर नारायण मिश्रा ने यह विवादाित फैसला दिया था। इस एकल पीठ का कहना था कि मामले में तथ्यों व आरोपों के आधार पर तय करना संभव नहीं है कि बलात्कार का प्रयास हुआ था। जिसके लिए अभियोजन पक्ष को सिद्ध करना था कि अभियुक्तों का यह कदम अपराध करने की तैयारी के लिए था। दरअसल, इसी के मद्देनजर देश में फैसले के खिलाफ तल्लख प्रतिक्रिया देखी गई। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ का कहना था कि दुराचार करने की कोशिश और अपराध की तैयारी के बीच के अंतर को सही ढंग से समझना चाहिए। हाईकोर्ट ने निचली अदालत को आईपीसी व पॉक्सो एक्ट की हल्की धाराओं में मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। उल्लेखनीय है कि यह घटना साल 2021 में एक नाबालिग लड़की के साथ हुई थी। जिसमें तीन युवकों ने लड़की से बदतमीजी की थी और उसके प्राइवेट पार्ट्स को छुआ तथा पुल के नीचे घसीटकर उसके पायजामे की डोरी तोड़ दी। जिसे पास से गुजरने वाले ट्रैक्टर चालकों ने बचाया था। स्थानीय पुलिस से जब किशोरी के परिजनों को मदद नहीं मिली तब उन्होंने न्याय के लिये कासगंज की विशेष अदालत का दरवाजा खटखटया था। जहां अभियुक्तों पर आईपीसी की धारा 376 व पॉक्सो एक्ट की धारा 18 लगाई गई। जिसको अभियुक्तों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसी मामले में आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ लोगों में नाराजगी देखी गई। माना गया कि इसका समाज में गलत संदेश जाएगा और महिलाओं की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इसके चलते ही एक महिला संगठन वी द वूमन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। कालांतर में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की उस टिप्पणी पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि केवल छाती पकड़ना, पायजामा का नाड़ा खींचना दुष्कर्म के प्रयास का अपराध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि टिप्पणी पूरी तरह असंवेदनशीलता और अमानवीय दृष्टिकोण को दर्शाती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में की गई विवादास्पद टिप्पणियों पर शुरू की गई स्वतः संज्ञान कार्यवाही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, यूपी सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है और फैसला सुनाने वाले न्यायाधीश की ओर से पूरी तरह असंवेदनशीलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि यह फैसले को लिखते हुए अपनाई गई असंवेदनशीलता को दर्शाता है। पीठ, जिसमें जस्टिस ऑगस्टीन और जॉर्ज मसीह भी शामिल हैं, ने कहा कि यह फैसला अचानक नहीं सुनाया गया। इसे सुरक्षित रखा गया और चार महीने बाद सुनाया गया। यानी कि इसमें दिमाग का इस्तेमाल किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, हम आमतौर पर इस स्तर पर आकर स्थगन देने में हिचकिचाते हैं, लेकिन टिप्पणियां कानून के दायरे से बाहर हैं और अमानवीय प्रतीत हो रही हैं, इसलिए हम इन टिप्पणियों पर स्थगन लगाते हैं। उल्लेखनीय है कि एक ऐसे ही मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के फैसले को पलटकर कानून की संवेदनशीलता को संबल दिया था। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2021 में कहा था कि किसी बच्चे के यौन अंगों को यौन इरादे से छूना पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 के तहत यौन हिंसा माना जाएगा। अब कहाे इसमें त्वचा का संपर्क नहीं हुआ हो। कोर्ट का मानना था कि अभियुक्त का इरादा ज्यादा मायने रखता है।

सत्ता का आसान रास्ता... इतिहास के गड़े-मुर्दे उखाड़ना

बेरोजगारी, गरीबी, अपराध, लिंगभेद, चिकित्सा जैसी आधारभूत सुविधाओं के समाधान के बजाए देश के नेता इतिहास के गड़े-मुर्दे उखाड़ कर वोट पाने का आसान रास्ता चुन रहे हैं। इसी क्रम में नया विवाद महाराणा सांगा पर दिए गए बयान पर पैदा हुआ है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में कहा कि बीजेपी के लोगों का यह तकियाकलाम बन गया है कि इनमें बाबर का डीएनए है। सपा सांसद रामजी लाल ने कहा कि मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को आखिर लाया कौन? इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा लाया था। उन्होंने कहा कि मुसलमान अगर बाबर की औलाद हैं तो तुम लोग उस गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, यह हिन्दुस्तान में तय हो जाना चाहिए कि बाबर की आलोचना करते हो, लेकिन राणा सांगा की आलोचना नहीं करते?

बेरोजगारी, गरीबी, अपराध, लिंगभेद, चिकित्सा जैसी आधारभूत सुविधाओं के समाधान के बजाए देश के नेता इतिहास के गड़े-मुर्दे उखाड़ कर वोट पाने का आसान रास्ता चुन रहे हैं। इसी क्रम में नया विवाद महाराणा सांगा पर दिए गए बयान पर पैदा हुआ है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में कहा कि बीजेपी के लोगों का यह तकियाकलाम बन गया है कि इनमें बाबर का डीएनए है। सपा सांसद रामजी लाल ने कहा कि मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को आखिर लाया कौन? इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा लाया था। उन्होंने कहा कि मुसलमान अगर बाबर की औलाद हैं तो तुम लोग उस गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, यह हिन्दुस्तान में तय हो जाना चाहिए कि बाबर की आलोचना करते हो, लेकिन राणा सांगा की आलोचना नहीं करते? सांसद सुमन की राज्यसभा में की गई टिप्पणी पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जो लोग आज नहीं बल्कि 1000 वर्षों के भारत के इतिहास की समीक्षा करते हैं, वे बाबर और राणा सांगा की तुलना कभी नहीं कर सकते और उन्हें एक ही तराजू पर नहीं रख सकते। महाराणा सांगा ने आजादी की अलख जगाई थी। उन्होंने भारत को गुलामी से बचाया और साथ ही भारत की संस्कृति को सनातनी बनाए रखने में भी अहम योगदान दिया। कुछ क्षुद्र और छोटे दिल वाले लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी चर्चाओं की कोई गुंजाइश नहीं है। यह पहला मौका नहीं है जब नेताओं ने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए इस तरह के विवादों को हवा दी है। इससे पहले भी ऐतिहासिक मुद्दों पर देश में दरार डालने के प्रयास होते रहे हैं। बॉलीवुड के निर्माता-निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को



लेकर भी काफी विवाद हुआ था, जिसमें राजपूत समुदाय ने फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया था। इस विवाद का परिणाम यह निकला कि चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित पद्मावती महल में अराजक तत्वों ने उन शीशों को तोड़ दिया, जिनके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हीं आईनों के जरिये राजपूत रानी पद्मावती को देखा था। इसी तरह तीन साल पहले बॉलीवुड फिल्म पानीपत से शुरू हुआ विवाद एक टीवी धारावाहिक तक आ पहुंचा। धारावाहिक में खांडेराव होल्कर से पूर्व महाराजा सूरजमल को युद्ध में हारना दिखाया गया। वहीं, इतिहासकारों का दावा है कि पूर्व महाराजा सूरजमल कभी युद्ध नहीं हारे। बल्कि खांडेराव होल्कर की मौत उनके साथ युद्ध में हुई थी। इसको लेकर रूपवास व कुम्हेर थाने में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई गईं। मैसूर के राजा रहे टीपू सुल्तान की 10 नवंबर को मनाई जाने वाली जयंती को लेकर भी खूब कलह हुआ है। मैसूर का शेर कहलाने वाले टीपू की जयंती की शुरुआत कांग्रेस के शासन में हुई लेकिन बीजेपी इसका विरोध करती रही।

कर्नाटक में टीपू सुल्तान की जयंती मनाने को लेकर नौबत यहां तक आ गई कि कई शहरों में सुरक्षा को देखते हुए धारा 144 लगाई गई और विरोध प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया। भारतीय जनता पार्टी और कुछ हिन्दू संगठनों ने सरकार से मांग की थी कि वह टीपू सुल्तान की जयंती मनाने का कार्यक्रम और उन्हें महिमाभिंडित करने की योजना रोक दें। बीजेपी की निगाह में टीपू सुल्तान धार्मिक रूप से कट्टर और हिन्दू विरोधी शासक था। भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने उत्तर भारत के 9वीं सदी के राजपूत शासक सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया और उन्हें एक गुज्जर बताया। दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) ने जौनपुर गांव में सम्राट मिहिर भोज की एक प्रतिमा भी समर्पित की, जिसमें उन्हें गुज्जर बताया गया। इसका राजपूत समुदाय ने कड़ा विरोध किया। बिहार में गठबंधन से पहले भाजपा ने नीतीश सरकार पर इतिहास के छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। भाजपा ने यहां तक कहा था कि सरकार ने प्रथम मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह का अपमान किया है। बिहार के पूर्व मंत्री भीम सिंह ने बिहार सरकार खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मोहम्मद युनुस को बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बताते हुए उनके जन्म दिवस पर राजकीय जयंती समारोह मनाए जाने को बिहार

केसरी श्रीकृष्ण सिंह का अपमान बताया था। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम तुष्टिकरण के तहत इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। गौरतलब है कि पिछले दिनों उत्तरप्रदेश के संभल जिले में मंदिर-मस्जिद विवाद पर नेताओं ने जम कर रोटियां सेकी। इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर हिंसा में पांच लोग मारे गए। इसके बाद देश के दूसरे हिस्सों में इसी तरह के विवाद पैदा हो गए। अजमेर में दरगाह में हिंदू मंदिर का दावा करते स्थानीय अदालत में मामला दायर किया गया। इसी तरह देश के दूसरे हिस्सों में भी मस्जिदों में मंदिर होने को लेकर अदालतों में मामले दायर किए गए। नेताओं ने तभी पैर पीछे खींचे जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे विवादों पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक पूजा स्थल अधिनियम की वैधता पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक देश में मंदिर-मस्जिद विवादों से जुड़े नए मुकदमे दर्ज नहीं किए जा सकते, और न ही कोई चल रहा मामला सर्वेक्षण या अंतिम आदेश के साथ आगे बढ़ सकता है।

यह विवाद पूरी तरह थमा भी नहीं कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद पैदा हो गया। इस पर भाजपा और विपक्षी दलों ने आरोप-प्रत्यारोप लगा कर देश का माहौल गर्माने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ी। इसका परिणाम यह हुआ कि नागपुर में हिंसा भड़क उठी। इसमें कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। आम लोगों को कर्फ्यू के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे विवादों की चपेट में अकसर देश का मजदूर, गरीब और कामकाजी वर्ग आता है। इन विवादों की जड़ में आसान सत्ता की राजनीति की चाहत है। दरअसल नेताओं को पता है कि देश की बुनियादी समस्याओं का समाधान आसान नहीं है, जबकि ऐसे विवादों के जरिये लोगों को बरगला लाकर सत्ता आसानी से प्राप्त की जा सकती है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के सदन में राणा सांगा पर दिए गए बयान पर बुधवार को बवाल हो गया। करणी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता कुबेरपुर से बुलडोजर, गाड़ियों और बाइकों पर सांसद के आवास पर पहुंच गए। पुलिस ने कई जगह रोकने की कोशिश की, लेकिन, वे बैरियर तोड़कर आगे बढ़ते रहे। संजय प्लेस स्थित एडीए के एचआईजी फ्लैट्स स्थित सुमन के आवास पर पहुंचकर कॉलोनी का गेट तोड़ने की कोशिश की। लाठी, डंडों से लैस हमलावरों ने सांसद आवास पर जमकर पथराव किया। शोशे चकनाचूर कर दिए। कुर्मियां और बाहर खड़ी सांसद सहित कई नेताओं की छह से अधिक

गाड़ियों के शोशे तोड़ डाले। पुलिस ने लाठियां भंजकर कुछ हमलावरों को हिरासत में ले लिया। सपा नेताओं ने थाना हरीपर्वत में तहरीर दी है।

सपा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही थीं। उनके घर पर हमला करने का ऐलान भी किया गया था। इस कारण उनके आवास पर पुलिस बल तैनात किया गया था। बुधवार को सुबह 11 बजे करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू प्रताप सिंह, युवा सेना के अध्यक्ष ओकेन्द्र राणा दो बुलडोजर, करीब 100 चार पहिया और दोपहिया वाहनों पर कार्यकर्ताओं के साथ एल्मादपुर स्थित यमुना एक्सप्रेस-वे के पुल के नीचे इकट्ठे हो गए थे। पुलिस ने उन्हें यहां रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह आगरा की ओर बढ़ते चले गए। रास्ते में भी हंगामा हुआ। वाटरवर्कस चौराहे पर कुछ वाहन चालकों से कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। आंबेडकर पुल से पालीवाल पार्क होकर काफिला जब एमजी रोड पर पहुंचा तो पुलिसकर्मियों ने आगे चल रही गाड़ी के आगे बैरियर लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों को धकियाकर बैरियर हटा दिए। इस दौरान पुलिस से झड़प में इस्पेक्टर आलोक सिंह व एक दरोगा सहित कई पुलिसकर्मियों को चोटें आईं। उधर इससे पहले महाराष्ट्र के नागपुर में हिंसा हुई थी। महाराष्ट्र में इस साल जनवरी से अब तक सांप्रदायिक तनाव की 823 घटनाएं सामने आई हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि इन घटनाओं में नागपुर में हाल ही में हुई हिंसा भी शामिल है। नागपुर में 17 मार्च को पथराव और आगजनी की घटना हुई थी। छत्रपति संभाजीनगर जिले में स्थित मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान पवित्र पुस्तक की पंक्तियां लिखी चादर जलाए जाने की अफवाह फैलने के बाद हिंसक भीड़ ने 17 मार्च को नागपुर के कई इलाकों में पथराव और आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया था। नागपुर हिंसा के दौरान पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) स्तर के तीन अधिकारियों सहित 33 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। हाल के दिनों में छत्रपति संभाजीनगर जिले में स्थित मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को गिराने की दक्षिणपंथी संगठनों की मांग को लेकर नंदुरबार, पुणे (ग्रामीण), रत्नागिरी, सांगली, बीड और सतारा जिलों के अलावा अन्य क्षेत्रों में सांप्रदायिक अशांति देखी गई।

मौसम का उलटफेर: मार्च में गर्मी और ठंड का अनोखा संगम

ग्लोबल वार्मिंग पर चिंता बनी महज़ सैमिनार का विषय?

मार्च का महीना आमतौर पर सर्दी से गर्मी की ओर संक्रमण का समय माना जाता है, लेकिन इस वर्ष मौसम के अप्रत्याशित बदलावों ने सभी को चौंका दिया है। एक ओर देश के कई हिस्सों में असामान्य हीटवेव देखी गईं, तो दूसरी ओर कुछ गर्म क्षेत्रों में बर्फबारी और ठंडे स्थानों पर गर्म हवाओं का अनुभव हुआ। विशेषज्ञ इन घटनाओं को जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के रूप में देख रहे हैं। गर्मी के मौसम में बर्फबारी, सर्दी के मौसम में तपिश, दिल्ली में मार्च में ही जून जैसी गर्मी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मार्च के महीने में तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। तपने के अंत तक, अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से काफी अधिक है। यह असामान्य गर्मी न केवल दैनिक जीवन को

प्रभावित कर रही है, बल्कि स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। शिमला में गर्म हवाएं, मनाली में बर्फबारी! हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, जो अपनी ठंडी जलवायु के लिए जानी जाती है, वहां भी मार्च में तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई। महीने के अंत में अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस पहाड़ी क्षेत्र के लिए असामान्य है। दूसरी ओर, मनाली और रोहतांग पास में अचानक बर्फबारी हुई, जिससे पर्यटक तो खुश हुए, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों को इस बदलाव ने हैरान कर दिया। राजस्थान में भीषण लू, मुंबई में असामान्य ठंडक- जयपुर में मार्च के दौरान तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे गर्मी से बेहाल लोगों ने अभी से ठंडे पेय और एयर कूलर

की शरण ले ली है। वहीं, मुंबई और गोवा जैसे तटीय क्षेत्रों में इस बार मार्च में अपेक्षाकृत ठंडक बनी रही, जो आमतौर पर गर्मी से जूझते इन शहरों के लिए असामान्य है। दुबई में आई बाढ़- जलवायु परिवर्तन की एक और चेतावनी- अगर जलवायु परिवर्तन को लेकर अब भी दुनिया ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, तो इसके और भी भयावह परिणाम देखने को मिल सकते हैं। पिछले वर्ष दुबई जैसे रेगिस्तानी इलाके में जबरदस्त बारिश और बाढ़ ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। दुबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में 24 घंटे में 140 मिमी से अधिक बारिश हुई थी, जो वहां के वार्षिक औसत से कहीं अधिक थी। दुबई, जो अपने शुष्क और गर्म मौसम के लिए जाना जाता है, वहां इस तरह की भारी बारिश और बाढ़ एक अप्रत्याशित घटना

थी। इसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन को बताया गया, जिसमें वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण मौसम के पैटर्न असामान्य रूप से बदल रहे हैं। दुबई की यह बाढ़ सिर्फ एक संकेत भर है कि जलवायु परिवर्तन अब केवल पहाड़ों और जंगलों तक सीमित नहीं है, बल्कि रेगिस्तानी इलाकों को भी प्रभावित कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की बातें-बस सेमिनार और वर्कशॉप तक सीमित? हर साल दुनिया के अनेक देशों में ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर लंबी-लंबी चर्चाएं होती हैं। संयुक्त राष्ट्र, विश्व पर्यावरण संगठन, इंटरगवर्नमेंटल पैनेल ऑन क्लाइमेट चेंज जैसी वैश्विक संस्थाएं वार्षिक रिपोर्टें जारी करती हैं। सरकारें जलवायु परिवर्तन पर सेमिनार आयोजित करती हैं, बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं,

लेकिन जब बात जमीनी स्तर पर अमल की आती है, तो वास्तविक प्रयास उतने प्रभावी नहीं दिखते जितने सेमिनार में किए गए दावे। ‘*COP सम्मेलनों’ के बड़े वादे, पर कार्रवाई धीमी- * हर साल जलवायु परिवर्तन पर COP सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, जहां दुनिया के बड़े नेता, वैज्ञानिक और नीति-निर्माता मिलकर कार्बन उत्सर्जन को कम करने, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण के उपायों पर चर्चा करते हैं। लेकिन इन सम्मेलनों में लिए गए फैसलों का क्रियान्वयन उतनी तेजी से नहीं हो रहा जितनी जरूरत है। कई देश अभी भी जीवाश्म ईंधनों (कोयला, पेट्रोल, डीजल) पर निर्भर हैं और ग्रीन एनर्जी की ओर शिफ्ट होने में बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। क्या अब भी वक्त बचा है? मौसम में इस तरह के असामान्य

बदलाव यह संकेत दे रहे हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को लेकर अब भी ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले वर्षों में स्थितियों और भी गंभीर हो सकती हैं। गर्मी के महीनों में बर्फबारी और ठंडे महीनों में लू चलने जैसी घटनाएं अब अपवाद नहीं, बल्कि एक नई जलवायु वास्तविकता बनती जा रही हैं। क्या किया जाना चाहिए? * पर्यावरणीय नीतियों का कड़ाई से पालन किया जाए। * उद्योगों को ग्रीन एनर्जी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। * कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सख्त नियम बनाए जाएं। * अधिक से अधिक वृक्षारोपण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाए। * जनता को भी जागरूक किया जाए ताकि वे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझें और उसमें अपनी भूमिका निभा सकें। निष्कर्ष इस बार मार्च के महीने में जलवायु का जो असामान्य मिजाज देखा गया, वह सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक गंभीर संकेत है कि अगर हमने अभी भी पर्यावरण संरक्षण को गंभीरता से नहीं लिया, तो आने वाले वर्षों में मौसम का यह असंतुलन जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करेगा। दुबई जैसी रेगिस्तानी जगहों पर बाढ़ आना और पहाड़ों में गर्म हवाएं चलना यह दर्शाता है कि मौसम अपने प्राकृतिक स्वरूप से बाहर जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि जलवायु परिवर्तन सिर्फ सेमिनार और सम्मेलनों का विषय न बने, बल्कि वास्तविक धरातल पर ठोस प्रयास किए जाएं ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और संतुलित वातावरण मिल सके। (राजीव खरे ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़)

जल शक्ति राज्यमंत्री ने किया सरकार के आठ वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन

वन विभाग उत्तर प्रदेश की आठ वर्ष में उपलब्धियों पर आधारित पुस्तिका का किया विमोचन

गौरव सिंघल । सिटी चीफ सहारनपुर, राज्यमंत्री, जल शक्ति विभाग उत्तर प्रदेश दिनेश खटीक द्वारा जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में सरकार के सेवा, सुरक्षा, सुशासन के आठ वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कम्पनी बाग में आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। इसी के साथ उन्होंने सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा सरकार की योजनाओं एवं उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उन्होंने कम्पनी बाग में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गये स्टालों का अवलोकन कर योजनाओं एवं उत्पादों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के 10 वर्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार के 08 वर्ष की उपलब्धियों एवं विकास कार्यों को बताया। उन्होंने देश एवं प्रदेश की बढ़ती हुई समृद्धि की सराहना की। सुरक्षित उद्यमी समृद्ध व्यापार गोष्ठी के अंतर्गत राज्यमंत्री द्वारा राम जी सुनेजा, उद्यमी अनूप खन्ना, रविंद्र मिगलानी, शीतल टंडन, अमित राणा, अनुराग सिंघल, विवेक



मनोचा, रोहित घई, जयवीर राणा, संजय अरोड़ा, अजय कालड़ा, मुकुंद मनोहर गोयल, नरेश धीमान, मंजीत अरोड़ा को प्रतीक चिन्ह एवं अंगवस्त्र भेंटकर सम्मानित किया गया। इसी के साथ व्यापारी दुर्घटना योजनांतर्गत राघव कालड़ा को 10 लाख का चेक दिया गया। कार्यक्रम में गुरुनानक गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राओं ने पंजाबी गिद्दा, रमा वर्मा ने सरस्वती वंदना, राजू ने भजन, शिवा रोशन, वैष्णवी नृत्यालय की साधिकाओं द्वारा रामायण गीत प्रस्तुत किए। इस अवसर पर नगर विधायक राजीव गुंबर,

जिलाधिकारी मनीष बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवाण, जिलाध्यक्ष भाजपा महेन्द्र सैनी, मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन, महानगर अध्यक्ष शीतल बिशोई, अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ० अर्चना द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रजनीश कुमार मिश्र, जिला सूचना अधिकारी दिलीप कुमार गुप्ता सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, उद्यमीगण तथा भारी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे।

श्री रामकृष्ण योगाश्रम इंटर कॉलेज कालेज की कक्षा 9 व 11 की कक्षाओं का परीक्षाफल घोषित किया गया

संस्था प्रबंधक साध्वी आशु एवं प्रधानाचार्य अरुण कुमार ने विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए

गौरव सिंघल । सिटी चीफ सहारनपुर । देवबंद, श्री रामकृष्ण योगाश्रम इंटर कॉलेज देवबंद के प्रधानाचार्य अरुण कुमार ने बताया कि आज कालेज की कक्षा 9 व 11 की कक्षाओं का परीक्षाफल घोषित किया गया है। जिसमें कक्षा 9 में वंशिका शर्मा पुत्री अमित शर्मा ने 1020 में से 809 अंक, कक्षा 9 व में सिया पुत्री विकास गाबा ने 1020 में से 823 अंक, कक्षा 9 सी में कीर्ति पुत्री जोगिंद्र ने 1020 में से 754 अंक प्राप्त कर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 11 अ में



काकुल राठी पुत्र मनोज ने 1000 में से 814 अंक, कक्षा

11 ब में शिवम पुत्र रविंद्र कुमार ने 1000 में से 826 अंक व कक्षा 11 सी में महिमा पुत्री जगमोहन वर्मा ने 1000 में से 719 अंक प्राप्त कर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस अवसर पर संस्था की प्रबंधक साध्वी आशु एवं प्रधानाचार्य अरुण कुमार ने विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर वरिष्ठ अध्यापक सुभाष चंद्र सहित समस्त विद्यालय परिवार उपस्थित रहा। इस दौरान सफल छात्र-छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामनाएं प्रकट की गईं।

सरकार महिलाओं को सुरक्षा के साथ दे रही सम्मान : राज्यमंत्री जसवंत सैनी

राज्यमंत्री ने किया सरकार के आठ वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन

गौरव सिंघल । सिटी चीफ सहारनपुर, राज्यमंत्री संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास जसवंत सैनी द्वारा सरकार के सेवा, सुरक्षा, सुशासन के आठ वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कम्पनी बाग में आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। इसी के साथ उन्होंने सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा सरकार की योजनाओं एवं उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उन्होंने कम्पनी बाग में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गये स्टालों का अवलोकन कर योजनाओं एवं उत्पादों की जानकारी ली। मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन द्वारा राज्य मंत्री को काष्ठ से निर्मित गणेश जी की प्रतिमा भेंट की गई। राज्य मंत्री ने केंद्र सरकार के 10 वर्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार के 08 वर्ष की उपलब्धियों एवं विकास कार्यों को बताया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं को सुरक्षा के साथ सम्मान देने का कार्य कर रही है। आज सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर प्रदेश के विकास में भागीदार बन रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, बेबी किट, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लाभार्थियों को लैपटॉप, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को नियुक्ति पत्र, संस्कृति विभाग द्वारा जनपद के प्रत्येक ब्लॉक की एक ग्राम पंचायत को हारमोनियम, डोलक, झीका, एक जोड़ी घुंघरू, एक जोड़ी मंजीरा आदि वाद्य यंत्रों का एक एक सेट वितरित किया गया। महिला सशक्तिकरण की थीम पर आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। डबल इंजन की सरकार जन कल्याण के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। यूपी देश के विकास का प्रोथ इंजन बन रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर कानून व्यवस्था के साथ ही महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सराहनीय



कार्य हुए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या सुमंगला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना एवं मिशन शक्ति अभियान के माध्यम से नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य सरकार द्वारा किया गया है। महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन के साथ ही होली एवं दीवाली पर निःशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल भी दिए जा रहे हैं। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से मातृ, शिशु एवं नवजात मृत्यु दर में कमी आई है। शहरों को सेफ सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। सरकार की विभिन्न योजनाओं से महिलाओं की आर्थिक उन्नति हो रही है। सरकार द्वारा प्रतिभाशाली छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना चलाई गई है। त्रिदिवसीय प्रदर्शनी के दौरान संस्कृति विभाग लखनऊ द्वारा नामित कवियों पदम गौतम एवं प्रवीण तोमर ने राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी कविताओं एवं नीरज सिंह ने रागिनी गायन के द्वारा सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। प्रवेश द्वारा गायन एवं रमेश कुमार द्वारा गायन तथा लोक नृत्य प्रस्तुत किए गए। मंच का सफल संचालन को राकेश शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पुलिस विभाग द्वारा साइबर क्राइम के बारे में बताते हुए उससे बचाव के बारे में जागरूक किया गया। जिला सूचना अधिकारी द्वारा राज्यमंत्री एवं उपस्थित अन्त्यों को विकास पुस्तिका प्रदान की गई। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष मांगेराम चौधरी, मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन, अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ० अर्चना द्विवेदी, जिला सूचना अधिकारी दिलीप कुमार गुप्ता सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण भारी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे।

आपसी सौहार्द के साथ मनाएं पर्व, गंगा-जमुनी तहजीब को हमेशा की तरह बनाए रखें - डीएम मनीष बंसल



अलविदा जुमा, नवरात्रि, ईद एवं राम नवमी की तैयारियों के संबंध में शांति समिति की हुई बैठक

गौरव सिंघल । सिटी चीफ सहारनपुर, जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलकट्रेट स्थित नवीन सभागार में अलविदा जुमा, नवरात्रि, ईद एवं राम नवमी के पर्व पर शांति एवं कानून व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों, संप्रदाय नागरिकों के साथ शांति समिति की बैठक की गयी। बैठक में समिति के सदस्यों से समस्याओं एवं निराकरण संबंधी सुझाव लेते हुए अनुश्रवण किया गया। डीएम मनीष बंसल ने कहा कि आपसी सौहार्द को बनाये रखते हुये मिलजुलकर एक-दूसरे का सहयोग करते हुए पर्व को मनायें। यह क्षेत्र हमेशा से आपसी भाईचारा व गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल रहा है। सभी धर्म अमन और शांति का संदेश देते हैं। अगर कहीं पर कोई समस्या या विवाद है तो जिला प्रशासन को अवगत कराए। समय रहते ही समस्या का उचित निस्तारण किया जाएगा। ऐसा कोई कार्य न करें जिससे दूसरे की धार्मिक भावनाएं आहत हों। अनावश्यक रूप से कोई नई परंपरा न डालें। नमाज निर्धारित परिसरों में ही अदा की जाए। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कहा कि सभी अधिकारी अपनी अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन करें। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्बाध विद्युत एवं जल आपूर्ति

सुनिश्चित करने के साथ साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था की जाए। मस्जिदों के आस-पास की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध सख्त चेकिंग अभियान चलाया जाए। क्षेत्र के प्रबुद्धजनों से संवाद बनाकर रखें। इसके साथ ही अपने क्षेत्रों में निरीक्षण कर चल रही तैयारियों को परखते रहें। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण करना सुनिश्चित करें जिससे पर्व सकुशल शांतिपूर्वक सम्पन्न हो सकें। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि समिति के सदस्यों एवं समाज के संप्रांत लोगों से संपर्क में रहकर आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ ही समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवाण ने कहा कि इस बात का ध्यान रखें कि त्योहारों को इस प्रकार से मनाया जाए कि किसी अन्य को असुविधा न हो। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि संबंधित क्षेत्रों का भ्रमण कर तैयारियों का जायजा लेकर समय रहते व्यवस्थाओं को पूर्ण किया जाए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ० अर्चना द्विवेदी, एसपी सिटी व्योम बिंदल, एसपी देहात सागर जैन, नगर मजिस्ट्रेट गजेन्द्र कुमार, समाज के प्रबुद्धगण सरफराज खां, सुरेंद्र कपिल, राजेश जैन, जयनाथ शर्मा, महेंद्र तनेजा, जामा मस्जिद प्रबंधक मौलवी फरीद, ब्रित चावला सहित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारीगण तथा शांति समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ की जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित

बैठक में जिला प्रधान सुरेन्द्र कौशिक द्वारा शमशेर पाल को प्रचार सचिव किया नियुक्त



अश्विनी वालिया । सिटी चीफ कुरुक्षेत्र, 27 मार्च ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ की जिला कार्यकारिणी की बैठक गुरुवार को जिला प्रधान सुरेन्द्र कौशिक की अध्यक्षता एवं प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी वालिया, प्रदेश उपाध्यक्ष देसराज भटनागर, प्रदेश मुख्य सलाहकार राजकुमार वालिया व प्रदेश मुख्य संरक्षक दलबीर मलिक के निर्देशन में संघ कार्यालय कुरुक्षेत्र सेक्टर-17 नजदीक पुराना बस स्टैंड के पास संपन्न हुई। बैठक में सर्वप्रथम गुजिया के साथ संघ के पदाधिकारियों का मुंह मीठा करवाया गया। इसके

उपरांत जिला प्रधान सुरेन्द्र कौशिक द्वारा जिला कार्यकारिणी में शमशेर पाल को प्रचार सचिव नियुक्त किया गया। इस अवसर पर प्रदेश उपप्रधान देसराज भटनागर, मुख्य सलाहकार राजकुमार वालिया, मुख्य संरक्षक दलबीर सिंह मलिक, जिला महासचिव गुलशन ग़ोवर ने नवनियुक्त सदस्य को बधाई व शुभकामनाएं दी। ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी वालिया ने बैठक में नए सदस्य की घोषणा करते हुए कहा कि आशा है नवनियुक्त जिला प्रचार सचिव निष्ठा व मेहनत

से संघ के हित में कार्य करेंगे और संगठन में समान विचारधारा वाले पत्रकारों को जोड़ने का कार्य करेंगे। इस अवसर पर संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपने-अपने विचार रखे और पत्रकार एकता संघ को प्रदेश के विभिन्न जिलों में नए जिलाध्यक्ष व ब्लॉक स्तर पर भी नए पदाधिकारियों की नियुक्ति करने की बात कही और संघ को मजबूत करने के प्रयास बारे में कहा गया। इसके साथ-साथ कहा गया कि प्रदेश के पत्रकारों की समस्याओं को सरकार से अवगत करवाया जाएगा और उन्हें हल करवाने का भी प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ के प्रदेश उपप्रधान डीआर भटनागर, मुख्य संरक्षक दलबीर मलिक, मुख्य सलाहकार राजकुमार वालिया के अलावा ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ कुरुक्षेत्र जिला के प्रधान सुरेन्द्र कौशिक, महासचिव गुलशन ग़ोवर, उपप्रधान संजीव कुमार, सचिव अजय शर्मा, संगठन सचिव अनिल वर्मा, कोषाध्यक्ष राजकुमार कौशिक, ऑफिटर राजेश भटनागर, प्रचार सचिव हरिदास, कुलवंत सिंह बग्गा, अरविंद मोहन शर्मा व अन्य सदस्य मौजूद रहे।

ढीमरखेड़ा में भीषण आग

3 एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक, लाखों का नुकसान



सुनील यादव । सिटी चीफ कटनी, कटनी जिले के ढीमरखेड़ा तहसील के अंतर्गत ग्राम झारा पानी में गेहूं की खड़ी फसल में भीषण आग लग गई। करीब 3 एकड़ खेत में आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान हो गया। बताया जाता है कि ग्रामीणों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी लेकिन फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंच सकी थी। ग्रामीणों ने खेत में लगी आग को काबू पाने का बहुत प्रयास किया लेकिन आग तेज होने की वजह से गेहूं की खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि यह आग पानी की मोटर से हटा शॉर्ट सर्किट की वजह से गेहूं की बलियों में आग पकड़ ली और यह आग धीरे

धीरे पूरे खेत में फैल गई ग्रामीणों और किसानों ने ऐ आग पर काबू पाने का बहुत प्रयास किया लेकिन आग तेज होने के वजह से 3 एकड़ की कड़ी फसल जलकर खाक हो चुकी थी। जिस खेत में आग लगी हुई थी यह खेत सुंदर लाल बंसंत यादव का खेत है। वही गेहूं की खड़ी फसलों में आग लगने के मामले में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि यदि किसान की फसल प्राकृतिक वजह से लगी है तो जिला प्रशासन किसान को मुवजे की राशि स्थानीय अधिकारी और पटवारी से सर्वे करा दी जाएगी। ओर यदि किसी के द्वारा फसल में आग लगाना पाया गया तो उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी।

कटनी के दिगम्बर जैन स्कूल में तहसीलदार की कार्रवाई

वेतन भुगतान को लेकर हुआ विवाद

सुनील यादव । सिटी चीफ कटनी, कटनी जिले के दिगम्बर जैन स्कूल के एक कर्मचारी को जीपीएफ फंड एवं वेतन दिए जाने के मामले में लेबर कोर्ट के एक फैसले को लेकर तहसीलदार बी के मिश्रा राजस्व अमले के साथ राशि की वसूली के लिए स्कूल पहुंचे। वही स्कूल पर ताला लगा देख तहसीलदार स्कूल गेट पर अपने अमले के साथ खड़े रहे और स्कूल के अध्यक्ष के आते ही अध्यक्ष स्कूल के गेट पर ही खड़े हो कटनी तहसीलदार से बात की ओर स्कूल के गेट का ताला भी नहीं खोला गेट पर ही पूरी चर्चाएं की। कटनी तहसीलदार बी के मिश्रा ने स्कूल के अध्यक्ष से दिगम्बर जैन शिक्षा संस्था को संबंधित कर्मचारी की राशि का भुगतान करने के लिए कहा। जो कि करीब दो लाख 7 हजार रुपये है। संस्था के अध्यक्ष आशीष जैन ने बताया कि लेबर कोर्ट के आदेश के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में



याचिका दायर की गई है, जहां प्रकरण लंबित है। इसके बावजूद संस्था कर्मचारी को राशि का भुगतान करने के लिए तैयार है

लेकिन संस्था के बैंक खाते को होल्ड किया गया है। वही एसडीएम प्रदीप मिश्रा ने बताया कि लेबर कोर्ट के आदेश का पालन कराने के

लिए तहसीलदार को भेजा गया था। लेकिन आज समय अधिक हो जाने के कारण कार्रवाई नहीं कि जा सकी है। इसके अलावा संस्था को

राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया है। यदि संस्था भुगतान नहीं करती है तो फिर कल आगे की कार्रवाई की जाएगी।

प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शिव वरदानी धाम शाजापुर में मनाया गया राजयोगिनी दादी जानकी जी का पांचवा पुण्य स्मृति दिवस

भगवान दास बैरागी । सिटी चीफ शाजापुर, उक्त श्रद्धांजलि कार्यक्रम में ब्रह्माकुमारी पूनम बहन जी ने राजयोगिनी दादी जानकी जी को श्रद्धांजलि देते हुए दादीजी जीवन के प्रसंगों का व्याख्यान किया, मुख्य रूप से उन्होंने बताया कि राजयोगिनी दादी जानकी जी बाल्यकाल में ब्रह्माकुमारी संस्थान के संपर्क में आए और उन्होंने संस्थान के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के जीवन से प्रेरणा लेते हुए ईश्वरीय सेवा में अपना संपूर्ण जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दिया।



श्रद्धांजलि देते हुए ब्रह्माकुमारी चंदा बहन जी ने बताया कि दादी जी 104 वर्ष की आयु में भी भारत के कई शहरों व विदेशों में ईश्वरीय संदेश देते हुए मनुष्य के चरित्र निर्माण का कार्य बखूबी निभाया और 104 वर्ष की दीर्घ आयु होते हुए भी विश्व भ्रमण करते हुए मानव कल्याण की सेवा करते रहे एवं 27 मार्च 2020 को उन्होंने अपना भौतिक देह त्याग किया। कार्यक्रम में

आगे ब्रह्माकुमारी दीपक भाई ने दादी जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि दादी जी ने मात्र 3 क्लास ही पढ़ाई किया था लेकिन भारत के कई नगर व महानगरों में सेवा करने के पश्चात संस्थान के द्वारा विदेशों में ईश्वरीय सनातन संस्कृति का संदेश देने हेतु सेवाओं का कार्य दादीजी को सौंपा गया इतनी कम शिक्षा होते हुए भी दादी जानकी जी ने निराकार परमपिता शिव भगवान

के दिव्य अवतरण का सन्देश ब्रह्माकुमारी संस्थान के माध्यम से विश्व के कोने कोने में पहुंचाया और शायद ही ऐसा कोई देश होगा जहां दादी जी ने ईश्वरीय सेवाएं न की हो और विश्व के लगभग 140 से भी अधिक देशों में संस्थांन के सेवा केंद्र स्थापित किये। व हजारों माता- बहनों, भाइयों को परमात्मा शिव के इस मानव कल्याण के कार्य में समर्पित

इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में छत्तीसगढ़ को मिला 3700 करोड़ के निवेश प्रस्ताव क्या इस बार साकार होंगे वादे?

राजीव खरे । सिटी चीफ बेंगलुरु, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बेंगलुरु में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में देश के नामी उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण बैठक में आईटी, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण और ग्रीन फ्यूल जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान विभिन्न कंपनियों ने 3700 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दिए, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब केवल खनिज संसाधनों के लिए नहीं, बल्कि तकनीक और नवाचार के केंद्र के रूप में भी उभर रहा है। सरकार की नई औद्योगिक नीति के तहत आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे स्टार्टअप और टेक कंपनियों को अनुकूल वातावरण मिलेगा। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने नैसकॉम, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन

(इडुध्र) और द इंडस एंटरप्रेन्योर्स (इडुध्र) बेंगलुरु के साथ रणनीतिक समझौते (स्वह) भी किए, जिससे राज्य में टेक्नोलॉजी सेक्टर को और मजबूती मिलेगी। बेंगलुरु की कई टेक और मैनुफैक्चरिंग कंपनियों ने छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर उत्सुकता दिखाई है। सरकार का कहना है कि निवेशकों को हर संभव सहयोग और सुविधाएं दी जाएंगी ताकि छत्तीसगढ़ को एक नई औद्योगिक पहचान मिले।

क्या इस बार निवेश हकीकत बनेगा या फिर कागजों तक ही सीमित रहेगा? हालांकि, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इससे पहले भी इन्वेस्टर मीट आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें कई कंपनियों ने रुचि दिखाई थी और एमओयू भी साइन हुए थे। लेकिन हकीकत यह रही कि ज्यादातर निवेश परियोजनाएं जमीनी स्तर पर पूरी नहीं हो सकीं। निवेश विभाग ने विधानसभा में पूछे गए प्रश्नों के जवाब देने में ही अपना समय बिताया, लेकिन उद्योगों के बड़े वादे कागजों पर ही रह गए। अब जबकि मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में सरकार फिर से निवेश को बढ़ावा

देने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है, उम्मीद की जा रही है कि इस बार निवेश केवल समझौतों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि व्यवहारिक रूप से धरातल पर भी उतरेगा। उद्योग जगत और सरकार के बीच हुए नए समझौते अगर हकीकत में बदले तो यह राज्य की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा और रफ्तार दे सकते हैं।

आशाएं और चुनौतियां छत्तीसगढ़ सरकार की औद्योगिक नीतियां और हालिया एमओयू आर्थिक विकास और रोजगार बढ़ाने के लिए अहम साबित हो सकते हैं, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या कंपनियों सच में अपने निवेश प्रस्तावों को मूर्त रूप देंगी। निवेशकों को न केवल अनुकूल वातावरण चाहिए, बल्कि सरकार से लॉजिस्टिक्स, भूमि आवंटन, टैक्स इंसेंटिव और नीति-निर्माण में पारदर्शिता जैसी सुविधाएं भी अपेक्षित हैं। अब यह देखने की बात होगी कि यह नई इन्वेस्टर मीट छत्तीसगढ़ के औद्योगिक भविष्य को किस हद तक प्रभावित कर पाती है। क्या इस बार निवेश हकीकत बनेगा या एक और वादा अधूरा रह जाएगा

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फैली अत्यवस्था को लेकर बैठे भूख हड़तालियों को जबरन उठा ले गई प्रशासन



सुशिल सोनी । सिटी चीफ कोतमा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फैली अत्यवस्था को लेकर पूर्व पार्षद भाजपा नेता देवशरण एवं दीपक पटेल अधिवक्ता को प्रशासन ने 27 मार्च को शाम 5:00 बजे जबरन उठाकर ले गये, बताया जाता है कि 24 मार्च से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वाई क्रमांक 10 पुराने भवन से रैली निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वाई क्रमांक 4 भवन के सामने भूख हड़ताल में फैली

अव्यवस्था को लेकर बैठे हुए थे जिनके स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था 27 मार्च को शाम 5:00 बजे जिला प्रशासन भूख हड़ताल में बैठे दोनों के पास पहुंचकर उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उठाकर ले गए हैं उनकी मांगों पर क्या कार्रवाई होगी या नहीं होगी यह तो आने वाला समय बताएगा किंतु जबरन उठाए गए हड़तालियन के कारण क्षेत्र में प्रशासन के विरुद्ध आक्रोश व्याप्त है।

शाला में पहला कदम एक अप्रैल से प्रवेश उत्सव

पिपलोदा - कलेक्टर राजेश बाथम के निर्देशानुसार तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रृंगार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में स्कूली शिक्षा विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा शाला में पहला कदम अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत 1 अप्रैल से स्कूल प्रवेश उत्सव का आयोजन किया जाएगा शासन के निर्देशानुसार जिले में अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न स्तरों पर जवाबदारी तय की गई है। जिस पर जनप्रतिनिधियों और आमजन के सहयोग की अपेक्षा की गई है।



जिला शिक्षा अधिकारी अनीता सागर एवं जिला परियोजना समन्वयक डॉ धर्मेश सिंह हाडा बताया कि शिक्षा के लोक व्यापीकरण का मुख्य उद्देश्य 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को कक्षा एक से 12 तक कक्षाओं में प्रवेश देकर उनकी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है इसी उद्देश्य को लेकर 1 अप्रैल 2025 में शासकीय शालाओं में प्रवेश उत्सव का आयोजन किया जाएगा प्रथम दिन नव प्रवेशित छात्रों को तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा तथा निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरित की जाएगी शाला प्रबंधन समितियों की बैठक आयोजित कर विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति एवं संख्या बढ़ाने पर समुदाय को जागृत किया जाएगा साथी शिक्षक हैंड ओवर -टेक ओवर प्रक्रिया के तहत, प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक कक्षा पांचवी उत्तीर्ण छात्रों के, स्थानांतरण प्रमाण पत्र नजदीकी माध्यमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक को हैंड ओवर करेंगे, इसी

पाराली से बनेगा हरित ईंधन छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा ग्रीन एनर्जी निवेश



राजीव खरे । सिटी चीफ रायपुर, छत्तीसगढ़ में हरित ईंधन के क्षेत्र में निवेश को लेकर उद्योग जगत की दिलचस्पी बढ़ रही है। बेंगलुरु में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से GPCR आर्या प्राइवेट लिमिटेड के दीपक अग्रवाल ने मुलाकात कर बताया कि उनकी कंपनी राज्य में पराली से कंप्रेसड बायो गैस (CBG) बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में CBG प्लांट लगाने की योजना है, जिससे किसानों को फसल अवशेषों से अतिरिक्त आमदनी मिलेगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। कंपनी ने हाल ही में बेंमेतरा जिले में इंडियन ऑयल के साथ मिलकर एक CBG प्लांट स्थापित किया है, जो अब पूरी तरह से कार्य करने की दिशा में

है। दीपक अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस परियोजना को सफल होने के बाद वे छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी इसी मॉडल को अपनाना चाहते हैं। इस पहल से जैविक ईंधन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य की भागीदारी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि सरकार हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति के तहत जैविक ईंधन और पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस बैठक में उद्योग जगत के अन्य प्रतिनिधियों ने भी छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर उत्सुकता जताई।

है। दीपक अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस परियोजना को सफल होने के बाद वे छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी इसी मॉडल को अपनाना चाहते हैं। इस पहल से जैविक ईंधन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य की भागीदारी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि सरकार हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति के तहत जैविक ईंधन और पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस बैठक में उद्योग जगत के अन्य प्रतिनिधियों ने भी छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर उत्सुकता जताई।

बीजापुर के सुदूर वनांचल में सुशासन का सूर्योदय

तिमेनार में पहली बार पहुंची बिजली

राजीव खरे । सिटी चीफ बीजापुर, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के अति सुदूर गांव तिमेनार में मुख्यमंत्री मजरा-टोला विद्युतीकरण योजना के तहत आजादी के 77 वर्षों बाद पहली बार बिजली पहुंची। यह ऐतिहासिक उपलब्धि माओवादी आतंक के अंधकार को चीरकर विकास, अमन और शांति के नए सवेरे की ओर कदम बढ़ाने का प्रतीक है। तिमेनार में अब भय की जगह उजाला और आतंक की जगह उम्मीद ने ले ली है। गांव के 53 घरों में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया है, जिससे पूरे गांव में हर्ष और उल्लास का माहौल है।

विकास की रोशनी से दूर हो रहा भय और असुरक्षा भैरमाड ब्लॉक के ग्राम पंचायत बेचापाल के आश्रित गांव तिमेनार के निवासियों ने पीढ़ियों तक बिजली की रोशनी नहीं देखी थी। अब, जब शासन-प्रशासन ने इन दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच बनाकर जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना शुरू किया है, तो ग्रामीणों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का सपना साकार हो रहा है। ग्रामीणों की जुबानी -अब डर नहीं लगता, खुशियों का उजियारा छाया है! गांव के निवासी मशराम, पंडर कुंजाम,



मंगली और प्रमिला वेको ने बताया कि गांव में पहली बार बिजली पहुंची है, अब रात के अंधेरे से डर नहीं लगता। जंगली जानवरों, सांप-बिच्छू के भय से भी मुक्ति मिली है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई आसान हो गई है, और अब हम भी विकास की दौड़ में शामिल हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अब न केवल आतंक और भय का माहौल समाप्त हो रहा है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता भी सुधर रही है।

मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता इन्हें हर गांव में विकास की किरण पहुंचेगी मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार प्रदेश के हर मजरा-टोला को विद्युतीकरण से जोड़ने और नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की धारा प्रवाहित करने के लिए संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने

कहा कि जहां कल तक नक्सली आतंक का साया था, वहां आज विकास की किरणें फैल रही हैं। यह परिवर्तन ही असली जीत है। तिमेनार में हुआ विद्युतीकरण बस्तर के दूरस्थ अंचलों में सुशासन और विकास के नए युग की शुरुआत का संकेत है। अब यह क्षेत्र माओवाद के डर से मुक्त होकर समृद्धि और उजाले की ओर अग्रसर हो रहा है।

गांवों में हो रहा बुनियादी सुविधाओं का विस्तार तिमेनार में विद्युतीकरण के साथ-साथ सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी हो रहा है। तिमेनार अब सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि बस्तर के बदलाव की जीवंत मिसाल बन गया है। जहाँ कभी अंधकार और आतंक का बोलबाला था, वहीं अब बिजली की रोशनी, बच्चों की मुस्कान और विकास की रफ्तार है। यह परिवर्तन केवल एक योजना की सफलता नहीं, बल्कि राज्य सरकार की प्रतिबद्धता, प्रशासन की सक्रियता और जनता के विश्वास का प्रतिफल है। तिमेनार में सुशासन से हो रहे बदलाव की यह यात्रा बताती है कि जब इरादे मजबूत हों और नीति जन-केंद्रित हो, तो कोई भी दुर्गमता विकास के रास्ते में बाधा नहीं बन सकती।

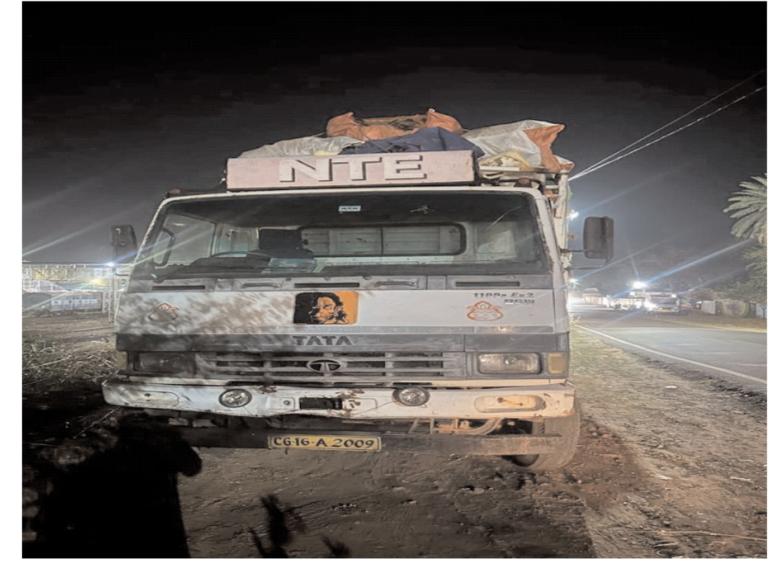
मामला संदेहास्पद

कबाड़ से भरा पिकप पुलिस ने पकड़ा बिना जांच किया वाहन को छोड़ा

सुशिल सोनी । सिटी चीफ कोतमा, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की ओर जाने वाली कबाड़ से भरा वाहन को पुलिस ने नेशनल हाईवे 43 में 26 एवं 27 तारीख की रात्रि को पकड़ लिया गया था जिसको थाना कोतमा में पदस्थ हवलदार संजीव त्रिपाठी द्वारा कुछ राशि जुर्माना कर वाहन को बिना जांच कर छोड़ दिया गया, बताया जाता है कि मुखबिर की सूचना पर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की ओर कबाड़ से भरा वाहन क्रमांक सीजी 16 ए 2009 टाटा पिकअप 26 एवं 27 की रात्रि जा रहा था कि पुलिस ने सूचना में मौके पर थाना कोतमा में पदस्थ हवलदार के पद पदस्थ संजीव त्रिपाठी पहुंचकर वाहन को बिना जांच किए कुछ जुर्माना करके छोड़ दिया जिस कारण से क्षेत्र वासियों में पुलिस के प्रति नाराजगी बताई जा रही है क्षेत्र वासियों का कहना है कि आए दिन रोज क्षेत्र में चोरी की घटनाएं घट

रही है साथ ही यह कोयलांचल क्षेत्र है खदानों में महंगे कल पुर्जे की उपयोगिता होती है जिसे कबाड़ियों द्वारा चोरी करके प्लास्टिक एवं अन्य सामान के अंदर छुपा कर बड़े शहरों में ले जाकर कीमती दरों में बेचा जा रहा है क्षेत्र में लगातार चोरियों पर अंकुश नहीं लग रहा है वहीं दूसरी ओर पुलिस ने कबाड़ से भारी वाहन को बिना जांच किए हुए ही छोड़े जाने के कारण क्षेत्र वासियों ने पुलिस के प्रति पुंदिह बना हुआ है स्थानीय जनों ने सुलेश कसना से मांग किया है कि कबाड़ से भारी वाहन को छोड़ने वाले के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए जिससे क्षेत्र में चोरियों पर अंकुश लग सके।

दिन में कबाड़ से भरा वाहन पकड़ा गया था जिसमें प्लास्टिक था जुर्माना करके वाहन छोड़ दिया गया है।



सुदेश सिंह थाना प्रभारी थाना कोतमा

मुख्यमंत्री कन्या विवाह/ निकाह योजना में प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने की शिरकत

झाबुआ आज जिले के झाबुआ जनपद पंचायत के गोपालपुरा ग्राम में मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के तहत मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव की गरिमा मय उपस्थिति में सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष भानु भूरिया ने शासन के अनगिनत योजनाओं के लाभ बताए। कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि यह योजना गरीब लोगों के लिए लागू की गई है। सांसद अनीता चौहान ने कहा कि आपके विवाह में स्वयं सीएम आए हैं इसलिए आप धन्य हैं। प्रभारी मंत्री



झाबुआ कुंवर विजय शाह ने कहा कि चांदी के गहने टंच हो, उन पर हॉलमार्क लगाया जाना आवश्यक है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पाणिग्रहण संस्कार सबसे बड़ा संस्कार है, गृहस्थ जीवन दो परिवारों का मिलन

का यह अवसर है। आपने जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की। सारे कार्यक्रम में जिला प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई। जिसमें जिले के सभी ब्लॉक के मिलकर 2000 से ऊपर जोड़ों ने विवाह का लाभ लिया।

झील कंपनी को भूमि आर्बिट जमीन का सीमांकन से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है

धार **सीमांकन के पर नाम गरीब लोगों की जमीन हथियाने पर सैकड़ों लोग हो जायेंगे बेघर झील कंपनी की बाउंड्री वाल से ग्रामीण कैदी का जीवन जीने को विवश - एक और दीवाल दूसरी और नदी**

कब्जा दिलाने गये अधिकारियों के समक्ष ग्रामीणों ने आक्रोशित झगडात पाडा के 20 से अधिक मकान मालिक को पट्टे दिए जाऐगे- तहसीलदार सुरेश नागर बदनावर। ग्राम छायन में स्थित झील कंपनी की सीमा से लगी हुई भूमि झील कंपनी को आर्बिट करने पर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। कब्जा दिलाने गये अधिकारियों के समक्ष ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर कहा कि झील कंपनी को अनाधिकृत रूप से जमीन आर्बिट की गयी। ग्रामीणों का जीवन संकट में आ गया है।



वर्षों से निवासरत लोगों को झील कंपनी द्वारा वालबाउंड्री निर्माण करने पर हम कैद हो जाएंगे। ग्रामीणों द्वारा प्रशासनिक अधिकारी एवं झील कंपनी के जिम्मेदारों से बात करना चाही किंतु दोनों ही जिम्मेदारों ने गरीब लाचार लोगों की बात नहीं सुनी। ग्रामीणों का कहना है हम लोग कैद हो गये है एक और झील कंपनी की बाउंड्रीवाल तो दूसरी और नदी होने से हम कैदी की जीवन जी रहे है। ग्राम छायन में झील कंपनी संचालित है। झील कंपनी को गरीबों को बेघर कर जमीन का कब्जा दिलाने प्रशासनिक अमला पहुंचा। सीमांकन के पर नाम गरीब लोगों की जमीन हथियाने का शडयंत्र रचा गया है। झगडात पाडा गांव के 20 से अधिक

मकानों को झील कंपनी ने कैद करने की योजना बनायी है। ये लोग अपनी मर्जी से कही आ जा नहीं सकेगें। मंगलवार को प्रशासनिक अमला सीमांकन करने पहुंचा। प्रशासन ने जमीन झील कंपनी को भूमि आर्बिट करना बताने पर ग्रामीण भडक गए। और प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करना चाही किंतु वे बात करने को तैयार नहीं थे। झगडात पाडा गांव के रहवासियों का कहना है कि हम लोग वर्षों से निवासरत है। हमारे मकान बने है। और कई परिवार के लोगों के रहने का एकमात्र आषियाना यही है। झील फेक्ट्री लगाने के नाम पर हम लोगों के पुस्तैनी मकान की भूमि भी अलट कर दी गयी। भूमि आर्बटन की हमे कोई सूचना नहीं दी गयी। झील



कंपनी के लोग व प्रशासन की मिलीभगत से हम लोग बेघर हो जाएंगे। ग्रामीणों द्वारा जमीन नहीं देने की बात करने पर उन्हे डराया धमकाया गया। झुटा प्रकरण दर्ज कर फसाने की बात कही गयी। ओर ग्रामीणों को डराने धमकाने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया।

जिला पंचायत सदस्य अशोक डावर भी मौके पर पहुंचे और उनकी प्रशासनिक अधिकारियों से काफी बहस हुई। डावर का कहना है बिना जनसुनवाई एवं बगैर दावा आपत्त लिए जमीन आर्बिट नहीं की जा सकती है। ग्राम सभा में बिना ठहराव प्रस्ताव के किसी भी गांव की जमीन नहीं ली जा सकती है। ग्राम पंचायत द्वारा जमीन वापस लेने का प्रस्ताव पास कर जिम्मेदारों को दिया गया है। फेक्ट्री को भूमि आर्बटन निरस्त किया जाए। प्रशासन द्वारा जबन गरीबों लोगों को बेघर करने का प्रयास किया जाने पर आंदोलन के बाध्य होना जाएगा। किसी भी स्थिति में ग्रामीण जमीन नहीं छोडेंगे। अधिकारी ध्यान दे व जमीन आर्बटन निरस्त करे। तहसीलदार सुरेश नागर का कहना है कि एमपीआइडीसी द्वारा झील कंपनी को भूमि आर्बिट की गयी है। झगडात पाडा के 20 से अधिक मकान मालिक को पट्टे दिए जाएंगे। आबादी क्षेत्र की जमीन झील कंपनी को नहीं दी जाएगी। किंतु अतिक्रमण कर कब्जा की जाने वाली भूमि से अतिक्रमण हटया जाएगा।

गणगौर, ईद, रामनवमी पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित

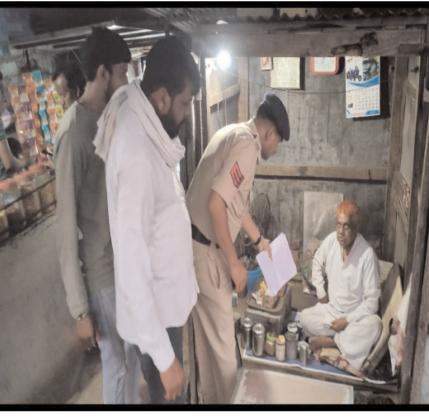
खरगोन कसरवाद थाना परिसर में एसडीएम सत्येंद्र बेरवा की अध्यक्षता में गणगौर, ईद, रामनवमी पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। ल्योहारों को सांप्रदायिक सौहार्द के बीच शांतिपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की गई। सभी ल्योहारों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि आगामी दिनों में आने वाले ल्योहार आपसी भाईचारे के साथ मनाना है। नगर में अमन एवं शांति बनी रहे। इसके लिए कोई भी व्यक्ति



ऐसा काम नहीं करेगा। जिससे समाज की शांति भंग हो। सभी लोग एक दूसरे के धार्मिक ल्योहारों एवं उत्सव का सम्मान करेंगे। इस दौरान एसडीएम सत्येंद्र बैरवा, एसडीओपी मनोहर सिंह

गवली, थाना प्रभारी राजेंद्र बर्मन, नायब, तहसीलदार, बिजली विभाग, एवं नगर परिषद के अधिकारी, गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, एवं पत्रकार बंधू मौजूद थे।

अवैध रूप से सट्टा लिखते पकड़ा, की कार्रवाई



खरगोन कसरवाद- थाना प्रभारी राजेंद्र बर्मन के निर्देशन में बुधवार को पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर बस स्टॉप के खरगोन रोड ग्राम सेलानी से आरोपी फखर्ददीन पिता याकुब खान उम्र 65 साल निवासी ग्राम चंदनपुरी कि पान टुकान से दविश देकर हारजीत कर रूपयो पैसो से मांग पत्तो का दावं लगाकर सट्टा खेलते आरोपी फखर्ददीन पिता याकुब खान उम्र 65 साल निवासी ग्राम चंदनपुरी को दविश देकर पकडा जिनके कब्जे

से एक लीड पेन, एक कार्वन का टुकड़ा, पांच सट्टा लिखि पर्विया ओर 1950 नगदी रुपये जफ्त किये तथा आरोपी के विरुद्ध धारा 4(क), सट्टा अधिनियम का प्रकरण पंजीब्द किया गया उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र बर्मन, जनि महेश यादव, सर्जनि आशीष पटेल, सर्जनि मोहन सिंगला, प्रआर. 31 अनिल परिहार, प्र आर 659 महेश मालवीया, आर.1045 अतुल, मआर.1033 सुनिधि का योगदान रहा।

नगर मे पंचकोशी यात्रा प्रवेश को लेकर समिति सदस्य निकले जनसहयोग के लिए

खरगोन कसरवाद - गुरुवार को सुबह 10:00 बजे राम मंदिर चौक प्रांगण से मां नर्मदा पंचकोशी यात्रा समिति सदस्यों द्वारा श्री गणेश किया गया 10 अप्रैल को पंचकोशी यात्रियों आगमन को लेकर समिति सदस्यों द्वारा नगर वासियों, प्रतिष्ठानों से सहयोग राशि इकट्ठा करने के लिए निकले पंचकोशी सदस्यों द्वारा मंडी प्रांगण में श्रद्धालुओं के लिए भोजन, प्रसादी, एवं टंडे जल की व्यवस्था रहेगी श्रद्धालु अजय मंडलोई द्वारा बताया गया कि यह यात्रा 41 वर्ष पहले प्रारंभ हुई थी। यह यात्रा महेश्वर प्राचीन ऐतिहासिक घाट से



प्रारंभ होती है जो चोली, मंडलेश्वर, जलुद, माकड खेड़ा, कसरवाद, बलगांव से होते हुए

पंचकोशी यात्री महेश्वर के प्राचीन एवं ऐतिहासिक घाट पर समापन होती है

मासूम बच्चों ने रखा रोजा, कर रहे हैं इबादत

खरगोन कसरवाद -- रमजान के पाक महीने में बच्चे भी रोजा रखकर इबादत कर रहे हैं। 6 से 10 साल के बच्चों ने भूखे रहकर अल्लाह की राह में रोजा रखा है। मुस्लिम इलाकों में रमजान की रौनक देखने को मिल रही है। जहां रमजान के पवित्र महीने में रोजो के साथ इबादत का दौर भी जारी है। इस पाक माह में बच्चे भी रोजा रख इबादत कर रहे हैं। 6 से लेकर 10 साल तक के बच्चों ने भी भूखे प्यासे रहकर अल्लाह की राह में



रोजा रख रहे है। मुस्लिम इलाकों में रमजान की रौनक घर से बाजारों तक में देखी जा रही है। रमजान और ईद की खरीदारी से बाजार भी गुलजार होते नजर आ रहे हैं। जमा मस्जिद मोहल्ले के 6 साल के मोहम्मद मुबाशिर अजमेरी ने पहला रोजा रखा साथ में

मोहम्मद मुजम्मिल अजमेरी, मोहम्मद अयाज खान, मोहम्मद शान खान, शाहाना खान सहित दर्जनों बच्चों भी रोजा रख रहे है। ये सभी न-?हे रोजेदारों ने भी अल्लाह की राह में अपनी भूख-प्यास मिटा दी और कम उम्र से ही रोजा रखना शुरू कर दिया। आज ये बच्चे अपने घर के बड़ों की तरह इबादत में अपना पूरा वक्त लो बिताते ही हैं, साथ ही स्कूल और अपने दोस्तों में नन्हे रोजेदारों के नाम से भी पहचाने जाने लगे हैं।

स्वीकृत ऋण प्रकरणों का अतिशीघ्र वितरण करें सुनिश्चित-कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल

रायगढ़ कलेक्टर श्री गोयल ने ली जिला स्तरीय परामर्शदात्री एवं पुनरीक्षण समिति की बैठक कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने कलेक्टरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय परामर्शदात्री एवं पुनरीक्षण समिति की बैठक ली। कलेक्टर श्री गोयल ने प्राथमिकता क्षेत्र की उपलब्धि, कमजोर वर्ग को ऋण, महिलाओं को ऋण, अल्पसंख्यक वर्ग को ऋण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, खादी ग्रामोद्योग, जिला व्यापार एवं उद्योग, अंत्योदय स्वरोजगार योजना एवं आदिवासी स्वरोजगार योजनाएं किसान क्रेडिट कार्ड जैसे विभिन्न योजनाओं विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने शासन की विभिन्न ऋण योजनाओं के बैंकों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए प्राथमिकता से निराकरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत श्री जितेन्द्र यादव



उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री गोयल ने बैंकों को प्रत्यक्ष कृषि ऋण के संबंध में बैंकवार समीक्षा करते हुए ऋण वितरण में बढोत्तरी के निर्देश दिए, इसके साथ ही उन्होंने आगामी खरीफ फसल बीमा की तैयारी करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार उन्होंने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की समीक्षा करते हुए कहा कि पात्र हितग्राहियों को सुगमता से ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के लंबित ऋण वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री गोयल ने खादी ग्रामोद्योग एवं जिला व्यापार एवं उद्योग, अंत्योदय स्वरोजगार योजना एवं आदिवासी स्वरोजगार योजना में प्राप्त प्रकरण एवं वितरण की जानकारी ली। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया

कि लंबित प्रकरण पर नियमित रूप से जानकारी लेते रहे। साथ ही स्वीकृत होने के पश्चात डिस्बर्समेंट अतिशीघ्र करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री गोयल ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन अंतर्गत जिले के विभिन्न बैंकों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन ग्रामीण एवं शहरी के जो प्रकरण लंबित है उन आवेदनों की जांच कर स्वीकृत करें अथवा आवेदन एवं दस्तावेज अपूर्ण होने की स्थिति में उन्हें अवगत कराते हुए पूर्ण करने में सहयोग करें, ताकि महिलाओं को अनावश्यक समस्या न हो। कलेक्टर श्री गोयल ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा बनाए गए केसीसी प्रकरण अद्यतन प्रगति की जानकारी ली। कलेक्टर श्री गोयल ने विभागों निर्देशित किया कि केसीसी के प्रकरण को अपने स्तर पर लंबित न रखे।

होली मिलन के साथ शपथ समारोह सम्पन्न



उज्जैन मध्यप्रदेश शिक्षक संघ की उज्जैन जिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम तथा होली मिलन समारोह मेलेख महादेव मन्दिर आलोट जागिर मे सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम मे भारतीय जनता पार्टी के उज्जैन ग्रामीण अध्यक्ष राजेश धाकड़ मुख्य अतिथी के रूप मे उपस्थित हुए, कार्यक्रम की अध्यक्षता नवनिर्वाचित शिक्षक संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह डोडिया ने की। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ संभागीय सचिव जगदीश सिंह केलवा द्वारा दिलाई गयी। कार्यक्रम को संभागीय अध्यक्ष सुभाषचन्द्र पाटीदार, संभागीय

संगठन मंत्री राजेन्द्र रावल, जिला संगठन मंत्री प्रवीण भाटी, तथा प्रदेश के समर्थ भारत आचाम के प्रमुख दिग्विजय सिंह चौहान ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन तहसिल सचिव नन्दराम अटोलिया ने किया। कार्यक्रम मे जिला सचिव महेश पाटीदार, जिला कोषाध्यक्ष सीताराम मिसोदिया, महिला शाखा प्रमुख ममता शर्मा, सुनील सोनाव, धिरेन्द्र सिंह पंवार, निर्भरराम अटोलिया, रामकिशन नायमा, भरत पाटीदार, गोबर्धन लाल सागित्रा, आनन्द मीणा, मुकेश रघुवंशी, भागोरथ नन्देड़, दीपक घोषा तथा सभी तहसील और विकासखण्ड के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित हुए। बैठक मे सदस्यता, शिक्षकीय समस्या और निदान तथा आगामी संघ के कार्यक्रमो की योजना बनाई गयी।

ओलंपियाड में प्रतिभागी सभी बच्चों ने जिले का नाम रोशन किया है - कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना

जर्मदापुरम सभी बच्चे खूब पढ़े एवं खूब खेले तथा भविष्य में हर परिक्षाओं में अव्वल स्थान प्राप्त करें ओलंपियाड और विज्ञान प्रदर्शनी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को कलेक्टर सभागार में किया गया सम्मानित जिले के 32 छात्रों ने हाल ही में आयोजित राज्य स्तरीय ओलंपियाड में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जबकि छात्र उदय नागले ने विज्ञान प्रदर्शनी में राज्य स्तरीय प्रथम स्थान प्राप्त किया। इन छात्रों को कलेक्टर सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना और मुख्य कार्यपालन अधिकारी सोजान सिंह रावत द्वारा प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला परियोजना समन्वयक डॉ. राजेश जायसवाल ने किया। कलेक्टर सुश्री मीना ने छात्रों और उनके पालकों के बीच समन्वय के महत्व को रेखांकित किया और शिक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। मुख्य कार्यपालन अधिकारी सोजान सिंह रावत ने बच्चों के आत्मविश्वास और निर्भीकता की सराहना करते हुए ओलंपियाड को ओलंपिक खेलों के समान महत्वपूर्ण बताया। सहायक परियोजना समन्वयक प्रभारी अकादमिक प्रदीप चौहान ने ओलंपियाड के तीन स्तरों की जानकारी दी, जिसमें कक्षा 2 और 3 के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण; और कक्षा 6 से 8 के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत



विषय शामिल थे। जिले स्तर पर प्रत्येक कक्षा और विषय से एक-एक विद्यार्थी का चयन राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए किया गया था। डॉ. राजेश जायसवाल ने बताया कि 20,775 बच्चों ने जन शिक्षा केंद्र पर प्रतिभाग किया, जिनमें से 3,570 छात्र विकासखंड स्तर पर थे। अंततः जिले स्तर पर 32 होनहार छात्रों का चयन हुआ। उन्होंने खुशी व्यक्त की, कि इनमें से ज्यादातर बच्चे पहली बार कलेक्ट्रेट नर्मदापुरम आए हैं। खूब खेले - खूब पढ़े सभी बच्चे - कलेक्टर कार्यक्रम के दौरान विज्ञान प्रदर्शनी एवं ओलंपियाड में जीतने वाले बच्चों से कलेक्टर ने कहा कि आप सभी बच्चों ने अपने अपने शिक्षकों माता-पिता, स्कूल, समाज तथा समस्त जिले को सभी को गौरवान्वित किया है। आप सभी पर हम सबको गर्व है। कलेक्टर ने कहा कि हम सभी को विश्वास है कि आप सभी भविष्य में भी इसी तरह जिले का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने बच्चों से कहा कि सभी बच्चे खूब खेले तथा खूब पढ़े लेकिन पढ़ाई मनोरंजन तथा खेलकूद सभी का समय निर्धारित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह समय आप सभी के लिए भविष्य निर्माण की दृष्टि से बहुत ही बहुमूल्य है। कलेक्टर ने कहा कि मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चों का जीवन में हर

प्रकार की परीक्षाओं में अव्वल स्थान प्राप्त करें। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बच्चों की इस उपलब्धि के लिए उनके शिक्षकों को भी शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह सब शिक्षकों की मेहनत का ही प्रतिफल है, शिक्षकों के ही कारण बच्चों का शैक्षणिक तथा व्यक्तित्व विकास होता है। उन्होंने कहा कि बच्चों की उपलब्धि पर इस प्रकार प्रोत्साहन देने से उनका मनोबल भी बढ़ता है इसलिए ऐसी गतिविधियां की जाती रहनी चाहिए। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में शिक्षकों के साथ ही बच्चों के अभिभावकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों में अच्छे संस्कार अंकुरित कर उनको सिंचित करने की जवाबदारी उनके माता पिता की ही होती है, मां-बाप ही होते हैं जो अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए अपना तन-मन-धन सब कुछ लगा देते हैं साथ ही कलेक्टर ने कहा कि बच्चों के अंदर सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना तथा जीवन जीने का सलीका एवं जीवन में आने वाली हर कठिनाइयों के सामना करना सिखाने की जिम्मेदारियां का निर्वहन भी माता-पिता ही करते हैं इसलिए मैं उन सभी को भी बच्चों के लिए उपलब्धि के लिए बहुत इसी बधाइयां एवं शुभकामनाएं। जिले की विभिन्न शासकीय शालाओं के कक्षा 2 से लेकर कक्षा आठवीं तक कुल 32 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया था जिनमें से 7 विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय के राज्य स्तरीय ओलंपियाड में हिस्सा लिया।

वीडियो कांफेसिंग के माध्यम से निर्देश

विदिशा राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव श्री विवेक पोरवाल ने आज वीडियो कांफेसिंग के माध्यम से राजस्व विभाग

से संबंधित क्रियान्वित विभिन्न बिन्दुओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव श्री पोरवाल

ने वन ग्राम से राजस्व लाइन दर्ज कराने की प्रक्रिया की निर्धारित बिन्दुओं पर समीक्षा की। विदिशा एनआईसी के अधिकारी श्री

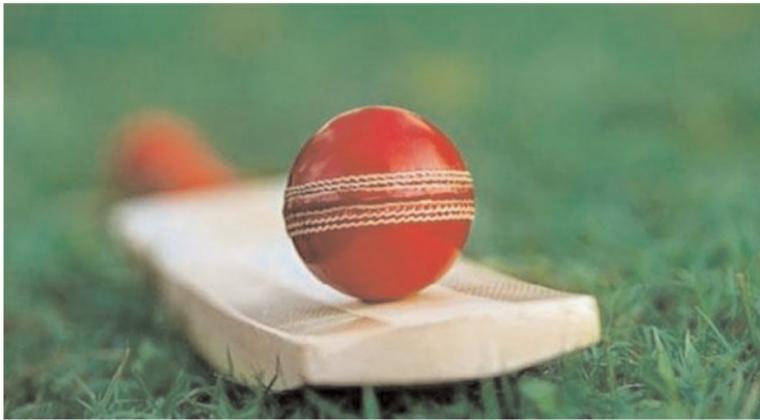
श्री रौशन कुमार सिंह, अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार डामोर, संयुक्त कलेक्टर द्वय श्रीमती मोहिनी शर्मा, सुश्री



निकिता तिवारी, अधीक्षक भू-अभिलेख श्रीमती कृष्णा रावत भी मौजूद रहें।

क्रिकेट जगत में शोक की लहर, दिग्गज खिलाड़ी का हुआ का निधन

नेशनल डेस्क. इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज तेज-मध्यम गेंदबाज पीटर लीवर का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है. इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है. पीटर लीवर इंग्लैंड के बेहतरीन गेंदबाजों में गिने जाते थे और उन्होंने अपने करियर में कई यादगार प्रदर्शन किए. पीटर लीवर का क्रिकेट करियर बेहद खास रहा. उन्होंने इंग्लैंड के लिए 1970 से 1975 के बीच 17 टेस्ट और 10 वनडे मैच खेले. अपने प्रेरक क्रिकेट करियर में उन्होंने लंकाशायर के लिए 301 प्रथम श्रेणी मैचों में शानदार 796 विकेट लिए. साथ ही, उन्होंने 3,534 रन भी बनाए.



पीटर लीवर को 1970 में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड XI के खिलाफ शानदार गेंदबाजी के लिए जाना जाता है. उन्होंने उस मुकामले में 7 विकेट झटकते थे और यह उनके करियर का टर्निंग पॉइंट

साबित हुआ. उन्होंने इस मुकामले में गैरी सोबर्स, क्लाइव लॉयड और मुस्ताक मोहम्मद जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को आउट किया था. बाद में लीवर ने कहा था, उन 7 विकेटों की बदौलत मुझे एशेज टीम में जगह मिली. **एशेज सीरीज में शानदार डेब्यू** पीटर लीवर ने 1970-71 एशेज सीरीज के दौरान इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया. उस सीरीज में इंग्लैंड ने शानदार जीत दर्ज की थी. इसके बाद, उन्होंने 1974-75 एशेज टॉर में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया और टेलबर्न टेस्ट में 6 विकेट लेकर टीम को पारी और 4 रन से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

हालांकि पीटर लीवर गेंदबाजी के लिए मशहूर थे, लेकिन उन्होंने 1971 में भारत के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड में 88 रनों की शानदार पारी खेली थी. उन्होंने रे इलिंगवर्थ के साथ मिलकर आठवें विकेट के लिए 168 रनों की साझेदारी की थी. यह उनके टेस्ट करियर की सबसे बेहतरीन पारियों में से एक मानी जाती है. **अंतरराष्ट्रीय करियर और संन्यास** अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में पीटर लीवर ने 17 टेस्ट और 10 वनडे खेले. टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 41 विकेट, जबकि वनडे में 11 विकेट अपने नाम किए. 1971 में उन्होंने अपना पहला

वनडे मैच खेला था. संन्यास के बाद भी उन्होंने क्रिकेट से अपना जुड़ाव बनाए रखा. वह लंकाशायर टीम के साथ जुड़े रहे और इंग्लैंड के चयनकर्ताओं के अध्यक्ष रे इलिंगवर्थकी भी मदद की. इसके अलावा, उन्होंने डेवन में स्थानीय क्लबों में कोचिंग देकर कई युवा खिलाड़ियों को क्रिकेट के लिए तैयार किया. **क्रिकेट जगत में शोक की लहर** पीटर लीवर के निधन से क्रिकेट जगत में शोक की लहर है. इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड सहित कई पूर्व और वर्तमान क्रिकेटर्स ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है. क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह एक बड़ी क्षति है.

भारत और चीन ने रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए उठाए कई अहम कदम

नेशनल डेस्क. भारत और चीन ने बुधवार को अपने द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के लिए कई कदम उठाने पर सहमति जताई। इनमें लोगों से लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने, सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने, मीडिया और थिंक टैंक के बीच संवाद बढ़ाने और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाने की योजना शामिल है। यह समझौता बीजिंग में दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच आधिकारिक परामर्श में हुआ, इसके एक दिन बाद सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यशील तंत्र की बैठक हुई, जिसमें सीमा पर सहयोग को फिर से शुरू करने पर चर्चा की गई, खासकर सीमा पर नदियों और कैलाश-मानसरोवर यात्रा के संबंध में। **सीमाओं पर स्थिति सुधारी** इन दोनों बैठकों का उद्देश्य भारत और चीन के रिश्तों को फिर से सामान्य करना था, जो लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों के बीच गतिरोध के बाद छह दशकों के निचले स्तर पर पहुंच गए थे। अक्टूबर में हुई एक समझौते के बाद, दोनों देशों के नेताओं ने एक दूसरे से मुलाकात की और रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए कई



पहलुओं पर सहमति जताई थी। **सीधे उड़ानें फिर से शुरू होंगी** बुधवार की बैठक में दोनों पक्षों ने विदेश सचिव विक्रम मिश्र और चीन के उप विदेश मंत्री सुन वेइडोंग के 27 जनवरी को हुई बैठक में तय रणनीतिक दिशा और कदमों की समीक्षा की। बैठक में यह भी तय किया गया कि लोग-से-लोग के बीच संपर्क को बढ़ाने के लिए सीधी उड़ानों की बहाली, मीडिया और थिंक टैंक के बीच संवाद और 75वीं वर्षगांठ की योजना पर काम जारी रहेगा। चीन ने इस बैठक में सीधी उड़ानों की बहाली

की प्रमुख मांग उठाई थी। इसके साथ ही चीन ने वीजा प्रतिबंधों को आसान बनाने और व्यापार संबंधों को फिर से शुरू करने की भी बात की थी। **कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली** बैठक में कैलाश मानसरोवर यात्रा को 2025 में फिर से शुरू करने के लिए भी आगे की प्रक्रियाओं पर चर्चा की गई। यह यात्रा 2020 से बंद थी और इसे फिर से शुरू करने के लिए दोनों देशों के बीच वार्ता चल रही है। **भविष्य के कदम** इस बैठक में यह भी चर्चा हुई कि

संवाद तंत्र को चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू किया जाए ताकि दोनों देशों के अहम मुद्दों पर बातचीत की जा सके और रिश्तों को एक स्थिर और पूर्वानुमान योग्य दिशा में ले जाया जा सके। गौरतलब है कि भारत-चीन के रिश्ते 1962 की सीमा युद्ध के बाद से सबसे खराब स्थिति में पहुंच गए थे, जब लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़पें हुईं और गलवान घाटी में जून 2020 में एक हिंसक संघर्ष में 20 भारतीय सैनिकों और कम से कम चार चीनी सैनिकों की मौत हो गई थी।

मिस्र के तट पर बड़ा हादसापर्यटक सबमरीन डूबी, 6 की मौत

काहिरा: मिस्र के हर्गहाडा शहर के पास 45 पर्यटकों को लाल सागर में प्रवाल भित्तियां दिखाने के लिए पानी के भीतर ले जा रही एक पनडुब्बी डूब गई, जिसमें छह रूसी मारे गए। यह जानकारी प्रांतीय गवर्नर ने दी। प्रांतीय गवर्नर ने बताया कि इनमें कई पर्यटकों को बचा लिया गया घटना में घायल हो गए हैं। रूसी वाणिज्य दूतावास ने बताया कि पनडुब्बी डूबने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। उसने बताया कि यह हादसा समुद्र तट से करीब 1,000 मीटर दूर हुआ। रूस की 'तास% समाचार एजेंसी ने हर्गहाडा में स्थित देश के वाणिज्य दूतावास का हवाला देते हुए पहले कहा था कि मृतकों में कम से कम दो बच्चे शामिल हैं। वाणिज्य दूतावास ने कहा था कि जहाज पर सवार सभी 45 पर्यटक रूसी थे, लेकिन मिस्र के गवर्नर ने कहा कि उनमें भारतीय, नावों के नागरिक और स्वीडिश नागरिक भी शामिल थे। गवर्नर मेजर



जनरल अम्र हनफी ने एक बयान में कहा कि जब पनडुब्बी डूबी तो उसमें 45 पर्यटक और मिस्र के चालक दल के पांच सदस्य सवार थे। उन्होंने कहा कि बचाव दल तुरंत भेजे गए। उन्होंने कहा कि सभी छह मृतक रूसी थे और बचाए गए 39 पर्यटकों में से 29 घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। उन्होंने कहा कि पनडुब्बी में सवार कोई भी व्यक्ति लापता नहीं है, जिससे पता चलता है कि चालक दल को भी बचा लिया गया है।

रूसी वाणिज्य दूतावास ने जिस कंपनी को पनडुब्बी संचालित करने वाला बताया है, उसकी वेबसाइट के अनुसार, सिंदबाद नामक यह पनडुब्बी एक से तीन घंटे का दूर संचालित करती है। इसके अनुसार यह पनडुब्बी आमतौर पर पानी के नीचे लगभग 20-25 मीटर पर चलती है और इसमें खिड़कियां होती हैं जिससे पर्यटक समुद्री जीवन देख सकते हैं। कंपनी से सम्पर्क करने के प्रयास किये गए लेकिन ऐसा अभी नहीं हो पाया।

जल्द ही मर जाएंगे पुतिन और खत्म हो जाएगा युद्ध, रूसी राष्ट्रपति की सेहत पर जेलेंस्की का बड़ा दावा

इंटरनेशनल डेस्क. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेहत को लेकर एक गंभीर दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पुतिन जल्द ही मर जाएंगे और इससे दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध का भी अंत हो जाएगा। यह टिप्पणी पुतिन की सेहत को लेकर चल रही अफवाहों के बीच आई है। पेरिस में एक इंटरव्यू के दौरान जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन की सेहत जल्द ही बिगड़ने वाली है और यह एक तथ्य है। बुधवार को फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए जेलेंस्की ने यह भी कहा, वो (पुतिन) जल्द ही मर जाएंगे, और यह एक तथ्य है। फिर इस युद्ध का भी अंत हो जाएगा। पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर पिछले कुछ महीनों से अफवाहों



और अटकलें चल रही हैं। हाल ही में उनके खांसने और उनके शरीर में झटके आने की कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई थीं, जिससे इन अफवाहों को और बल मिला। एक वीडियो में पुतिन को अपने पूर्व रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के साथ बैठक करते हुए देखा गया था, जिसमें वह टेबल को

पकड़कर बैठे थे और उनकी स्थिति भी सामान्य नहीं लग रही थी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि पुतिन पार्किंसन रोग और कैंसर से पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है और क्रेमलिन ने इन अफवाहों का खंडन किया है।

दूध के बाद बड़े दही के दाम, जानें क्या होंगे नए रेट

नेशनल डेस्क. आम जनता से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। कर्नाटक राज्य में दूध की कीमत में 4 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। चस्त्र यानि की कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ने गुरुवार को अपने ब्रैंड नंदिनी के नाम से बिकने वाले दूध के रेट को सीधा 4 रुपए बढ़ाए हैं। कीमत बढ़ोतरी के बाद टोन्ड मिल्क की कीमत अब 46 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जो पहले 42 रुपए थी। वहीं होमोजीनाइज्ड दूध की कीमत 47 रुपए हो गई है, जो पहले 43 रुपए थी। गाय के दूध की कीमत में भी 4 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। यानि की अब इसकी कीमत 50 रुपए हो गई है, जो पहले 46 रुपए थी। **शुभम दूध और दही के दाम भी बढ़े** शुभम दूध की कीमत 48 रुपए से बढ़कर 52 रुपए हो गई है। इसके अलावा, दही की कीमत भी 50 से बढ़ाकर 54 रुपए कर दी गई है। इन बढ़ी हुई कीमतों का असर ग्राहकों पर पड़ेगा, खासकर उन परिवारों पर जो रोजाना दूध और दही का सेवन करते हैं। दूसरी डेयरी कंपनियां भी बढ़ा सकती हैं दाम



नंदिनी दूध की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद, अन्य प्रमुख डेयरी कंपनियों जैसे अमूल, मदर डेयरी और सुधा भी दूध के दाम बढ़ने का अनुमान हैं। इन कंपनियों द्वारा दाम बढ़ाए जाने से देशभर के दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की कीमतों में असर पड़ सकता है।

नए बाजारों में विस्तार के लिए रणनीति केएमएफ के अनुसार, बढ़ी हुई दूध की कीमतें नए बाजारों में विस्तार करने के लिए एक रणनीति के रूप में काम करेंगी, क्योंकि उनका एक्स्ट्रा दूध अब विभिन्न राज्यों में बेचा जा सकेगा।

बलूचिस्तान में नहीं थम रहा आतंक

विद्रोहियों ने बस पर किया हमला, 6 लोगों की मौत

इंटरनेशनल डेस्क . पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में संदिग्ध उग्रवादियों ने पंजाब प्रांत के छह लोगों को एक यात्री बस से नीचे उतार लिया और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, पांच यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य ने बाद में दम तोड़ दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) हफ्ताज बलूच ने बताया कि यह हमला प्रांत के ग्वादर जिले में उस समय हुआ जब बुधवार देर रात हथियारबंद लोगों ने ओरमारा राजमार्ग पर



कलमत क्षेत्र के पास ग्वादर से कराची जा रही एक यात्री बस को रोक लिया। बंदूकधारियों ने बस से कुछ यात्रियों को उतारा और छह लोगों को गोली मार दी। बलूच ने बताया कि पांच यात्री मौके पर ही मारे गए, जबकि जीवित बचे एक व्यक्ति की बृहस्पतिवार सुबह अस्पताल में मौत हो गई। उन्होंने कहा, "हथियारबंद लोगों ने यात्रियों के पहचान-पत्र जांचने के बाद छह यात्रियों की हत्या कर दी और तीन अन्य को अपने साथ ले गए। उन्होंने कहा कि सभी पीड़ित पंजाब प्रांत के थे। फिलहाल किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी

नहीं ली है। उग्रवादियों ने ग्वादर बंदरगाह से खाद ले जा रहे तीन ट्रकों को भी सड़क पर अवरोध लगाकर रोक लिया और उनमें आग लगा दी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यात्री बस पर हमले की निंदा की और संबंधित अधिकारियों को जांच करने के साथ ही जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाने का निर्देश दिया। 'डॉन अखबार ने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के हवाले से कहा, "आतंकवादी देश के विकास और बलूचिस्तान की समृद्धि के दुश्मन हैं। वे बलूचिस्तान में प्रगति नहीं देख सकते। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती

ने घटना की निंदा करते हुए कहा, "निर्दोष यात्रियों को बस से उतारना और पहचान के आधार पर उनकी हत्या करना एक जघन्य और कारयतापूर्ण कृत्य है। यहां बुधवार को बस यात्रियों पर हमला ऐसे समय में हुआ है जब प्रांत में तनावपूर्ण स्थिति है, क्योंकि इस महीने की शुरुआत में प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के विद्रोहियों ने 440 यात्रियों को ले जा रही जाफर एक्सप्रेस का अपहरण कर लिया था। इस अपहरण में 18 सुरक्षाकर्मियों सहित 26 बंधकों की मौत हो गई थी।